राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण गुरुवार 27 नवम्बर 2025 वर्ष-8,अंक-270 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

मांगों को लेकर फिर किसान नेताओं ने दी सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी

27 को जालंधर स्थित नेशनल हाईवे को पूरी तरह किया जाएगा जाम

चंडीगढ़ पंजाब में एक बार फिर किसान आंदोलन की आहत सुनाई देने लगी है। बताया जा रहा है कि शंभु व खन्नौरी बार्डर के किसान संगठनों ने बड़े आंदोलनों का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं करती है, तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। किसानों ने बताया कि 27 नवंबर यानी गुरुवार को जालंधर स्थित नेशनल हाईवे को पूरी तरह जाम किया जाएगा। किसान नेताओं का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से कई बार मांगें उठाने के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके कारण अब उन्हें सड़कों पर उतरकर विरोध करना पड़ रहा है। वहीं किसान संगठनों ने 5 दिसंबर को पूरे पंजाब में दो घंटे के लिए ट्रेनें रोकने का भी फैसला लिया गया है। इस दौरान राज्यभर में रेलवे स्टेशनों पर किसान प्रदर्शन करेंगे। यह 'रेल रोको' की चेतावनी का पहला चरण है, ताकि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से ले। किसानों ने एलान किया कि 17 और 18 दिसंबर को पंजाब के हर जिले में डीसी दफ्तरों के बाहर धरना दिया जाएगा। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 18 दिसंबर तक भी उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई, तो वे 19 दिसंबर से राज्यभर में 'रेल रोको' आंदोलन शुरू कर देंगे। यह तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं निकालती। किसानों ने कहा कि वे बिजली संशोधन बिल 2025 का पुरज़ोर विरोध करेंगे, इसके साथ कई मुद्दों को लेकर भी संघर्ष किया जाएगा।

बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर पीएमओ ने इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश

मानदंडों का उल्लंघन करने वाले सभी वाहनों की जांच और उन पर कार्रवाई की जाए

नई दिल्ली दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार कई कदम उठा रही है। कुछ दिन पहले ही राजधानी में ग्रैप-3 लागू किया है। अब पीएमओ ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दोहरी रणनीति पर काम करने का निर्देश दिया है। पीएमओ ने एक उच्च-स्तरीय बैठक की, जिसकी अध्यक्षता पीएम के प्रधान सचिव ने की और प्रदूषण से निपटने के लिए कई सख्त निर्देश दिए। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब राजधानी की हवा की गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है। पीएमओ ने अधिकारियों को दो मुख्य मोर्चों पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि प्रदूषण फैलाने वाले और उत्सर्जन मानदंडों का उल्लंघन करने वाले सभी वाहनों की जांच और उन पर कार्रवाई की जाए। केंद्र सरकार दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना चाहती है, इसलिए चर्चा का एक अहम हिस्सा ईवी पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार पर केंद्रित था। पीएमओ ने अधिकारियों को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशन और सब्सिडी पर तेजी से प्रगति करने का निर्देश दिया। पीएमओ ने यह भी निर्देश दिया कि पारंपरिक पेट्रोल और डीज़ल वाहनों पर निर्भरता कम की जाए। यह कदम दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत दिल्ली के परिवहन को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा।

सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर निकला यूनिटी मार्च, सीएम ने की शुरुआत

यह यात्रा आणंद, वडोदरा और नर्मदा के तीन जिलों से होकर गुजरेगी

आनंद गुजरात के आनंद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष में बुधवार को यूनिटी मार्च निकाला। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस यात्रा की शुरुआत की। करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक एकता और अखंडता के मजबूत संदेश के साथ आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पदयात्रा आणंद, वडोदरा और नर्मदा जिलों से होकर गुजरेगी। यह यात्रा करीब 150 किलोमीटर की दूरी तय करके राष्ट्रीय एकता की भावना को उजागर करेगी। इस राष्ट्रीय पदयात्रा के दौरान, अखंड भारत के निर्माता और लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन मूल्यों, आदर्शों, सिद्धांतों और उनके विराट व्यक्तित्व को कथाओं और प्रवचनों के जरिए लोगों के दिलों में जीवित रखने के लिए कुल 11 सरदार गाथा सभाओं और 10 ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया है। यूनिटी मार्च के अंतर्गत आयोजित होने वाली यह राष्ट्रीय पदयात्रा न केवल एकता और अखंडता का प्रतिबिंब बनेगी, बल्कि राज्य के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के समान पांच नदियां भी इस ऐतिहासिक पदयात्रा की साक्षी बनेंगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाने वाली यह यात्रा आणंद, वडोदरा और नर्मदा इन तीन जिलों से होकर गुजरेगी और इस दौरान गुजरात की पांच पवित्र एवं सांस्कृतिक रूप से अहम नदियां इसकी गवाह बनेंगी। इन नदियों में मही, विश्वामित्री, जांबुआ, ढाढर और राज्य की जीवनरेखा (जीवादोरी) समान नर्मदा शामिल हैं।

आज का भारत केवल बड़े सपने नहीं देख रहा, बड़े फैसले भी ले रहा है: पीएम मोदी

पीएलआई स्कीम ने ग्लोबल मैन्युफैक्ररर को मेक इन इंडिया की तरफ किया आकर्षित

नई दिल्ली

पीएम मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत ने दुनिया को संदेश दिया है कि भारत निवेश और इनोवेशन का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि पीएलआई स्कीम ने ग्लोबल मैन्युफैक्ररर को मेक इन इंडिया की ओर आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाई है। बीते 11 सालों में 40 हजार से ज्यादा अनुपालनों को कम किया गया है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ने अनेकों अप्रोच को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने हैदराबाद में सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया (एसएईएसआई) फैसिलिटी के उद्घाटन पर अपने वर्चुअल संदेश में कहा कि आज का भारत केवल बड़े सपने नहीं देख रहा, बड़े फैसले भी ले रहा है और उनसे भी बढ़कर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है। भारत का फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर है।

उन्होंने कहा कि आज से भारत का एविएशन सेक्टर एक नई उड़ान भरने जा रहा है। सफ्रान की नई फैसिलिटी भारत को एक ग्लोबल एमआरओ हब के रूप में स्थापित करेगी। हाई टेक और एयरो स्पेस की दुनिया में युवाओं के लिए नए अवसरों को पेश करेगी।

उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए स्वतंत्र भारत में कुछ बड़े सुधार किए गए हैं।

अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले गए हैं, फंडामेंटल को मजबूत किया है और बिजनेस को आसान बनाया है। पीएम मोदी के मुताबिक डिफेंस जैसे सेक्टर जहां पहले प्राइवेट सेक्टर की जगह नहीं थी वहां भी अब 74 फीसदी तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से संभव हो गया है।

स्पेस सेक्टर में बड़ी अप्रोच अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि भारत के एविएशन सेक्टर में तेजी से विस्तार के चलते मेनटेनेंस,

रिपेयर और ओवरहॉल (एमआरओ) की सुविधाओं की जरूरतें बढ़ रही हैं। भारत की एयरलाइन कंपनियों ने 1500 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है।

दो प्राचीन सभ्यताओं से हमारे पास सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने की क्षमता है

चीनी राजदूत ने कहा- भारत-चीन सीमा विवाद जटिल मुद्दा, ढूंढ लेंगे समाधान

नई दिल्ली

भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने कहा है कि भारत-चीन सीमा विवाद एक जटिल मुद्दा है और इसका समाधान होने में काफी समय लगेगा। हालांकि दोनों देश सीमा को लेकर विशेष प्रतिनिधियों के स्तर पर बातचीत कर रहे हैं और सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए लगातार संपर्क में हैं।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूद जटिल सीमा मुद्दा और विशिष्ट मतभेद द्विपक्षीय संबंधों को परिभाषित नहीं करते हैं और न ही इन मुद्दों को सहयोग में बाधा बनना चाहिए। चीनी दूत फेइहोंग का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारतीय नागरिक पेमा वांगजोम थोंगडोक के मुद्दे पर भारत ने चीन को फटकार लगाई। थोंगडोक 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थीं। उन्होंने दावा किया कि उनका तीन घंटे का ठहराव किसी बुरे सपने जैसा था जब आव्रजन अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को सिर्फ इसलिए अवैध घोषित कर दिया क्योंकि उसमें अरुणाचल प्रदेश उनका जन्मस्थान लिखा था। इसके बाद भारत ने चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया और उसे इंटरनेशनल कानूनों की याद दिलाई।

राजदूत शू ने कहा कि यह दृष्टिकोण दोनों देशों के मूल हितों और उनके लोगों की साझा आकांक्षाओं के अनुरूप है। बिना किसी देश का नाम लिए उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत और चीन मिलकर बहुपक्षीय व्यवस्था की रक्षा करेंगे और एकतरफा वर्चस्व को अस्वीकार करेंगे। शू ने कहा कि चीन-भारत सीमा मुद्दा बहुत जटिल है और इसका समाधान होने में अभी काफी समय लगेगा, लेकिन मेरा मानना है कि दो प्राचीन सभ्यताओं के रूप में हमारे पास सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने और एक निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने की पर्याप्त बुद्धिमानी और क्षमता है। उन्होंने वर्तमान सीमा स्थिति को स्थिर बताया।

राजनयिक सूत्रों का मानना है कि राजदूत शू के बयान दो संकेत

देते हैं कि बीजिंग सीमा विवाद को अलग-थलग रखकर सहयोग के नए क्षेत्रों पर आगे बढ़ना चाहता है। चीन यह संदेश भी दे रहा है कि साझा वैश्विक चुनौतियों और भू-राजनीतिक हालात में भारत और चीन की भूमिकाएं अहम हैं। हालांकि भारत ने कई अवसरों पर साफ कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति और स्थिरता ही द्विपक्षीय संबंधों के आगे बढ़ने की आधारशिला है। 2020 के पूर्वी लद्दाख गतिरोध के बाद से दोनों देशों के संबंधों में तनाव बना हुआ है।

संविधान का अक्षरशःपालन हुआ तो 2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्रः ओम बिरला

नई दिल्ली

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को कहा कि यदि देश संविधान में निहित सिद्धांतों का पूरी निष्ठा से पालन करे, तो वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य साकार किया जा सकता है।

संविधान सदन (पुराना संसद भवन) के केंद्रीय कक्ष में आयोजित संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने लंबे विचार-विमर्श और व्यापक बहस के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया, जिसने भारत को एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने की मजबूत नींव रखी। बिरला ने कहा कि भारतीय संविधान एक जीवंत और गतिशील दस्तावेज है, जो नागरिकों की आवश्यकताओं और उनके अधिकारों का ध्यान रखता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान का पालन करना हर नागरिक और संस्था का कर्तव्य है, क्योंकि यही देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने का सबसे मजबूत आधार है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि संविधान सभा द्वारा संविधान अंगीकार किए जाने की स्मृति में 2015 से हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है।

केंद्र सरकार के नए श्रम कानून के खिलाफ 10 कर्मचारी संगठनों ने उठाई आवाज

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने नया श्रम कानून लागू कर दिया है और इसमें कई सुधार किए हैं। शुरुआत में इसे कर्मचारियों के हित में बताया जा रहा था, लेकिन अब कई कर्मचारी संगठनों ने इसकी खामियों पर सवाल उठाए हैं। नए लेबर कोड के खिलाफ 10 ऐसे संगठन हैं, जो इसे कर्मचारियों के हित में नहीं मान रहे और कंपनियों के लिए ज़ेयादा फायदा बता रहे हैं। यह सभी संगठन मिलकर बुधवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

ऐसे ही एक संगठन हिंद मजदूर सभा के महासचिव हरभजन सिंह का कहना है कि नया श्रम कानून कर्मचारियों के हितों की पूरी तरह से रक्षा करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोर्ड, 2020 के कुछ प्रावधान और वर्किंग कंडीशन कोड, 2020 के ऑक्वे यूपेशनल सेफ्टी जैसे प्रावधान कर्मचारियों के हित में नहीं है। इसमें सुधार के लिए दोबारा अपील और ड्राफ्टिंग होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि नए लेबर कोड में कारखानों को बंद करने, हड़ताल के अधिकार और छोटे उद्यमों के लिए अनुपालन बोझ को कम करने से जुड़े प्रावधान सीधे तौर पर श्रमिकों के जीवन और उनकी सामाजिक सुरक्षा पर असर डालते हैं। उन्होंने कहा कि हमने इस बारे में सरकार को बताया था, लेकिन हमारी चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए एकतरफा तरीके से कानून लागू कर दिया गया। हिंद मजदूर सभा उन 10 ट्रेड यूनियन में शामिल हैं, जिन्होंने अपने सदस्यों से 26 नवंबर को श्रम कानून के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। उन होंने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी के बीच इस तरह का कोड लागू होना कर्मचारियों के खिलाफ है। हिंद मजदूर सभा समेत 10 कर्मचारी यूनियन ने भले ही नए लेबर कोड का विरोध किया है, लेकिन कई अन्य संगठनों ने इस कानून का समर्थन भी किया है। इन संगठनों का कहना है कि नया लेबर कोड ऐतिहासिक और प्रगतिशील है।

26/11 बरसी: गृह मंत्री ने आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर दिया जोर

कहा आतंकवाद किसी एक देश के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए अभिशाप

नई दिल्ली

मुंबई में 26/11 हमलों की आज यानी बुधवार को 17वीं बरसी है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जोर दिया।

बता दें 10 आतंकवादियों का एक ग्रुप 26 नवंबर, 2008 की रात को समुद्री रास्ते से मुंबई में घुसा और अगले 60 घंटों तक एक के बाद एक कई हमले किए, जिसमें 166 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। ताज और ओबेरॉय होटल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, नरीमन हाउस, कामा हॉस्पिटल, मेट्रो सिनेमा और लियोपोल्ड कैफे टारगेट पर थे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह ने बुधवार को कहा कि मोदी सरकार की आतंकवाद को बिल्कुल न बर्दाश्त करने जीरो-टॉलरेंस की नीति स्पष्ट है और पूरा विश्व भारत के आतंकवाद रोधी अभियानों की तारीफ कर रहा है और उसे व्यापक समर्थन दे रहा है। मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों में अपने जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शाह ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि आतंकवाद किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए अभिशाप है।

गृहमंत्री शाह ने कहा कि 2008 में आज ही के दिन आतंकियों ने मुंबई पर कायराना हमला किया था। उन्होंने कहा कि मुंबई आतंकी हमलों का डटकर सामना करते हुए अपना बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन करता हूं और इस कायराना हमले में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं।

भारत-अफगानिस्तान संबंधों में आई नई गर्माहट से पाकिस्तान चिंतित

नई दिल्ली

अफगानिस्तान के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अज़ीज़ी की भारत यात्रा ने भारत-अफगानिस्तान संबंधों में नई गर्माहट ला दी है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच इतने बड़े स्तर पर व्यावहारिक प्रगति दर्ज की गई है। इस प्रगति से पाकिस्तानी शीर्ष नेतृत्व में काफी चिंता देखी जा रही है। अफगानिस्तान के मंत्री अज़ीज़ी ने घोषणा की कि भारत-अफगान वीज़ा संबंधी मुद्दे पूरी तरह सुलझा लिए गए हैं, और अब अफगान व्यापारी और आम नागरिक काबुल स्थित भारतीय दूतावास से आसानी से व्यापारिक और चिकित्सा वीज़ा प्राप्त कर सकेंगे। चिकित्सा वीज़ा की बहाली विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अफगान नागरिकों के लिए सबसे भरोसेमंद चिकित्सा गंतव्य माना जाता है।

इस यात्रा के दौरान व्यापार, कनेक्टिविटी, बैंकिंग, एफएसएसएआई शुल्क में छूट, संयुक्त वाणिज्य मंडल और संयुक्त कार्य समूह को सक्रिय करने सहित कई अटके हुए मुद्दों पर अहम सहमति बनी। दोनों देशों के बीच कपड़ा व्यापार बढ़ाने को लेकर भी उच्चस्तरीय वार्ता हुई। अफगानिस्तान भारत की कपास और परिधान क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ उठाना चाहता है, खासकर इसलिए क्योंकि भारत वर्तमान में अफगानिस्तान के लिए कपड़ा-परिधान का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।

यहां बताते चलें कि अज़ीज़ी ने भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर द्विपक्षीय व्यापार को 1 अरब डॉलर से अधिक तक ले जाने का लक्ष्य दोहराया। अफगानिस्तान ने भारत को खनन, कृषि, स्वास्थ्य और निवेश क्षेत्रों में नए अवसर प्रदान करने की इच्छा जताई है। सीमा तनाव और व्यापार रुकावटों के बीच काबुल ने यह भी संकेत दिया कि पाकिस्तान पर अत्यधिक निर्भरता अब उसके लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान-अफगान सीमा पर हालिया झड़पें और हजारों ट्रकों का फंसना काबुल के इस रुख को और मजबूत करता है।

विशेष रूप से, अज़ीज़ी के बयान– भारत बेहतर गुणवत्ता और बेहतर शर्तों वाला साझेदार है, ने दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। पाकिस्तान की ट्रांज़िट शक्ति को चुनौती देते हुए भारत-अफगान एयर कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट मार्ग और मध्य

एशिया के जमीनी मार्गों को पुनः सक्रिय करने की दिशा में नया मोड़ देखने को मिला है। अफगानिस्तान द्वारा पाकिस्तान की दवाइयों के आयात पर तीन माह का अस्थायी प्रतिबंध भी इसी रणनीतिक पुनर्संतुलन का संकेत माना जा रहा है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संविधानः लोकतंत्र की आत्मा और सुशासन का आधार

(लेखक - ललित गर्ग)

संविधान दिवस- 26 नवम्बर 2025)

संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण भी यही रहा कि संविधान तभी सफल होगा जब उसके अनुयायी चरित्रवान, प्रतिबद्ध और राष्ट्रहित साधक हों। बाबा साहेब ने कहा था-卐संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वह खराब सिद्ध होगा।卐 उनका यह चिंतन आज सबसे अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने संविधान को बनाया, पर उससे भी अधिक उन्होंने एक नैतिक चेतना जागृत की कि संविधान की शक्ति उसके लेखों में नहीं, बल्कि उस नागरिक चेतना में है जो उसे पालन करने के लिए तैयार रहती है। अंबेडकर का यह भी आग्रह था कि संविधान को केवल राजनीतिक बहस का साधन न बनाया जाए, बल्कि समाज सुधार और मनुष्य निर्माण की दिशा में उसका प्रयोग हो।

संविधान किसी भी राष्ट्र का चरित्र, मर्यादा और दिशा निर्धारित करता है। यह केवल विधिक दस्तावेज नहीं होता, बल्कि एक जीवंत मूल्य-व्यवस्था होती है जो राष्ट्र की आत्मा को परिभाषित करती है। संविधान दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र की स्थिरता, एकता और प्रगति का आधार हमारे संविधान की दूरदर्शिता, उदारता और संतुलन है। इसलिए किसी भी राष्ट्र में सुशासन की पहली और अनिवार्य शर्त यही है कि संविधान सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहे, केवल शासन के लिए ही नहीं, बल्कि नागरिक जीवन के हर व्यवहार, आचरण और विचार में भी।

भारत गणराज्य का संविधान 26 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ॰ भीमराव आंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवम्बर 2015 से भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस सम्पूर्ण भारत में हर वर्ष मनाया जा रहा है। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवम्बर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया और 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया।

भारत का संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत एवं आधुनिक संविधानों में माना जाता है। यह हमें केवल अधिकार ही नहीं देता, बल्कि कर्तव्यों की भावना भी जगाता है। यह हमें समानता, न्याय और स्वतंत्रता से सज्जित करता है, साथ ही यह भी बताता है कि इन आदर्शों को जीवित रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। जब किसी राष्ट्र में संविधान की अवहेलना शुरू होती है, तब लोकतंत्र डगमगाने लगता है। इसलिए संविधान का सम्मान करना एक विधिक प्रक्रिया का पालन मात्र नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चरित्र की बुनियाद है। आज संविधान दिवस पर यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि संविधान की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही दृढ़ता से बनी हुई है या नहीं? उत्तर स्पष्ट है-हाँ, क्योंकि हमारा समाज परिवर्तनशील है, चुनौतियाँ बदलती हैं, लेकिन न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल आदर्श समय से परे हैं। संविधान की उपयोगिता तभी सिद्ध होती है जब शासनकर्ता उसे सर्वोपरि मानें और नागरिक उसे जीवन का नैतिक मार्गदर्शक बनाएं।

इसी संदर्भ में यह भी विचारणीय है कि संविधान को केवल हाथ में लेकर जगह-जगह प्रदर्शन करना, जैसाकि कुछ राजनीतिक नेता, विशेषकर राहुल गांधी, करते हैं, क्या सचमुच संविधान के सम्मान का प्रतीक है? संविधान की प्रति का सार्वजनिक प्रदर्शन तब सार्थक होता है जब उसके मूल्यों को जीवन में उतारा जाए, उसके अनुच्छेदों का पालन किया जाए, उसके प्रति संयम, गरिमा और श्रद्धा रखी जाए। संविधान को राजनीतिक हथियार बनाकर भीड़ भावनाओं को उकसाने का प्रयास, संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। संविधान को मंचों पर लहराना सम्मान नहीं, बल्कि उसकी गंभीरता का अवमूल्यन है। संविधान कोई राजनीतिक पोस्टर या प्रदर्शन की वस्तु नहीं, वह राष्ट्र की मर्यादा का दस्तावेज है, जिसे विवेक, संयम और ईमानदारी से समझने एवं पालन करने की आवश्यकता होती है।

संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण भी यही रहा कि संविधान तभी सफल होगा जब उसके अनुयायी चरित्रवान, प्रतिबद्ध और राष्ट्रहित साधक हों। बाबा साहेब ने कहा था-'संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वह खराब सिद्ध होगा।' उनका यह चिंतन आज सबसे अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने संविधान को बनाया, पर उससे भी अधिक उन्होंने एक नैतिक चेतना जागृत की कि संविधान की शक्ति उसके लेखों में नहीं, बल्कि उस नागरिक चेतना में है जो उसे पालन करने के लिए तैयार रहती है। अंबेडकर का यह भी आग्रह था कि संविधान को केवल राजनीतिक बहस का साधन न बनाया जाए, बल्कि समाज सुधार और मनुष्य निर्माण की दिशा में उसका प्रयोग हो। उनके अनुसार संविधान को समझना यानी भारतीय समाज की आत्मा को समझना।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संविधान को सर्वोच्च सम्मान देते हुए उसे शासन का आधारस्तंभ बनाया है। वे बार-बार कहते रहे हैं कि 'संविधान हमारी शासन-व्यवस्था का पवित्र ग्रंथ है।' उनकी दृष्टि में संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं बल्कि अच्छे शासन, सामाजिक विश्वास और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। संसद के आरंभिक सत्र हों, प्रमुख राष्ट्रीय अवसर हों या आम जनता से संवाद, हर बार उन्होंने संविधान को सर्वोच्च स्थान दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि 'संविधान का पालन करना केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति का सर्वोच्च रूप है।' उनकी सरकार की प्राथमिकता यही रही है कि प्रत्येक नीति, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक योजना संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो। मोदी के नेतृत्व में कई ऐसे प्रयास हुए जिनका उद्देश्य संविधान के प्रति जन-जागरण बढ़ाना था, जैसे 'संविधान के प्रति कर्तव्य पालन' अभियान, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करना, पारदर्शी शासन एवं नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। उन्होंने संविधान दिवस को केवल समारोह न बनाकर राष्ट्रीय आत्मचिंतन का पर्व बनाने का प्रयास किया, जिससे हर नागरिक संविधान को केवल पढ़े नहीं बल्कि महसूस करे, समझे और जिए।

संविधान का सम्मान केवल शासन की जिम्मेदारी भर नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। यदि नागरिक संविधान को केवल विद्यालयों की पाठ्यपुस्तकों में सीमित मानते रहेंगे, तो यह राष्ट्र अपने लोकतांत्रिक आदर्शों से दूर होता जाएगा। संविधान का वास्तविक सम्मान तब है जब हम अपने दैनिक जीवन में समानता का पालन करें, न्याय को महत्व दें, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि रखें, किसी के साथ भेदभाव न करें, हिंसा या अराजकता के बजाय संवाद एवं शांति का मार्ग चुनें। आज जब दुनिया में असहिष्णुता, चरमपंथ और राजनीतिक कटुता बढ़ रही है, तब हमारा संविधान एक शीतल छाया की तरह हमें संरक्षण देता है। यह हमें बताता है कि राष्ट्र केवल सत्ता परिवर्तन का खेल नहीं बल्कि मूल्यों की निरंतरता है। संविधान इन्हीं मूल्यों को स्थिर रखता है।

संविधान दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि संविधान का सम्मान केवल राष्ट्रीय पर्वों पर नहीं बल्कि प्रतिदिन के जीवन में होना चाहिए। नागरिकों के मन में संविधान के प्रति आदर की आदत विकसित हो, यह तभी संभव है जब समाज में संवैधानिक शिक्षण को मजबूत किया जाए, देश के नागरिकों को अधिकारों के साथ कर्तव्यों का बोध कराया जाए और हर स्तर पर संवैधानिक आचरण को प्रोत्साहित किया जाए। आज आवश्यकता है कि संविधान को राजनीतिक विवादों से ऊपर उठाया जाए। उसे नारा, प्रदर्शन और विरोध की वस्तु न बनाया जाए। बल्कि उसे एक ऐसे प्रकाश स्तंभ के रूप में देखा जाए जो हमें न्यायपूर्ण, समतामूलक और शांतिपूर्ण समाज की ओर ले जाता है। यदि हम संविधान का सम्मान करेंगे तो राष्ट्र मजबूत होगा; यदि हम इसकी अवमानना करेंगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा।

संपादकीय

खतरनाक मंसूबे

नापाक पाक की ओर से सीमावर्ती राज्य पंजाब को अस्थिर करने की साजिश पिछली सदी से लगातार की जा रही है। लेकिन अब नशे का नश्तर सुनियोजित ढंग से इसके सीने पर जिस ढंग से चलाया जा रहा है, वह परेशान करने वाला है। पंजाब के पाक सीमा से लगे जिलों में नशीले पदार्थों की आपूर्ति लगातार जारी है। लेकिन अब इस साजिश में एक विचलित करने वाला अनैतिक मोड़ देखने को मिल रहा है। इसमें पाक स्थित ड्रग माफिया भारतीय सीमा में नाबालिगों को एक नशा आपूर्तिकर्ता के तौर पर भर्ती कर रहे हैं। यह कोई मामूली साजिश नहीं है, बल्कि एक खतरनाक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये तकनीकी बदलावों, कानून की खामियों और सबसे बढ़कर बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाने का कुत्सित प्रयास ही है। दरअसल, सीमा पार बैठे नशा माफिया कानून के छिद्रों व परिस्थितियों का लाभ उठाने से नहीं चूकते। अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का के किशोरों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। इन किशोरों में कई आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों से हैं। जिन्हें चंद रुपयों का प्रलोभन दिया जाता है। उन्हें स्मार्टफोनों का लालच भी दिया जाता है। इसके अलावा जो किशोर नशे की दलदल में धंस चुके हैं उनकी कमजोर नस को पकड़कर उन्हें मुफ्त ड्रग्स का लालच दिया जाता है। किसी भी देश के किशोरों का नशे के संजाल में फंसना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चे भविष्य के भारत के कर्णधार होते हैं। यदि वे अभी से नशे की दलदल और नशीले पदार्थों की आपूर्ति में लग जाएंगे तो देश-समाज का भविष्य कैसा होगा, अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। जिस काम को किशोर लालच से अंजाम दे रहे हैं, सही मायनों में वह बेहद खतरनाक है। वे ड्रोन से गिराए गए हेरोइन के पैकेट व कुछ मामलों में खतरनाक अवैध हथियार उठाते हैं और उन्हें ड्रग माफिया द्वारा बताए गए एजेंटों तक पहुंचाते हैं। दरअसल, आमतौर पर किशोरों की सामान्य सक्रियता को संदिग्ध नहीं माना जाता। उनका साफ-सुथरा रिकॉर्ड उन्हें कानून प्रवर्तन अधिकारियों की नजर से बचा लेता है। यदि नाबालिगों की गिरफ्तारी होती भी है तो वे भारतीय कानूनों के हिसाब से गंभीर सजा से बच जाते हैं। इस तरह, उनकी कम उम्र ही उन्हें सीमा पार बैठे नशे के तस्करों के लिये उपयोगी बना देती है। इन बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करते समय प्रवर्तन एजेंसियों को उदार रवैया अपनाना चाहिए। दरअसल, कुछ बच्चे परिस्थितियों के मारे भी होते हैं। वे मूलतः अपराधी नहीं होते। कुछ शातिर अपराधी उनका इस्तेमाल करके इस अपराध की दलदल में धकेल देते हैं। सही मायनों में वे सीमा पार से रची गई साजिश और हमारी अपनी व्यवस्था की कमजोरियों के कुचक्र व उससे उपजी आपराधिक व्यवस्था में आसानी से फंस जाते हैं। असल में, भारतीय किशोर न्याय कानून का उद्देश्य नाबालिगों को सुधारना और सुरक्षा करना होता है। लेकिन इस कानून की मूल भावना का लाभ संगठित नेटवर्कों द्वारा अपने मंसूबों को अंजाम देने को उठाया जा रहा है। हम 21वीं सदी में नशे की तस्करी का मुकाबला बीसवीं सदी के उपायों से नहीं कर सकते हैं। कभी-कभार होने वाली गिरफ्तारियां, छिटपुट छापे और उदार चेतावनी अपर्याप्त कही जा सकती हैं। निश्चित रूप से अपराध की घातकता के अनुरूप ही प्रतिक्रिया देने की जरूरत है।

संवैधानिक प्रावधानों से पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था सुनिश्चित हो

(लेखक- राजकुमार सिन्हा)

पारदर्शी व्यवस्था में संविधान का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह एक मूलभूत ढांचा प्रदान करता है जो सरकार के कार्यों को परिभाषित और सीमित करता है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है और सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। संविधान सरकार के विभिन्न अंगों (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) की शक्तियों और कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। यह शक्तियों के केंद्रीकरण और दुरुपयोग को रोकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी कार्य कानून के अनुसार हों। संविधान कानून के शासन को स्थापित करता है, जिसका अर्थ है कि देश पर शासन व्यक्तियों की मनमानी से नहीं, बल्कि स्थापित कानूनों से चलेगा। यह एक समान और निष्पक्ष व्यवस्था बनाता है। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिनकी रक्षा सरकार को करनी होती है। सूचना का अधिकार जैसे प्रावधान, जो अक्सर संवैधानिक सिद्धांतों से प्रेरित होते हैं, नागरिकों को सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार देते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।पारदर्शिता और जवाबदेही सुशासन के दो प्रमुख तत्व हैं। संविधान ऐसा प्रावधान करता है जो सरकारी निकायों को उनके निर्णयों और कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह बनाता है, जैसे कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) जैसे संवैधानिक निकायों की स्थापना। जब सरकार संविधान द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार पारदर्शी तरीके से काम करती है, तो नागरिकों का सरकार में विश्वास बढ़ता है। यह व्यवस्था को वैधता प्रदान करता है और सरकार व लोगों के बीच विश्वास पैदा करता है। पारदर्शिता भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। संवैधानिक ढांचा सरकार के हर स्तर पर खुलेपन और ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा देता है। संविधान एक पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणाली की नींव के रूप में कार्य करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार जनहित में और कानून के दायरे में काम करे।सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार नागरिकों को सरकार के कामकाज के बारे में जानने का हक देता है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।सरकारी योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन करने से प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है और नागरिकों के लिए सूचना तक पहुंच आसान हो गई है। केंद्र सरकार ने कई कल्याण योजनाओं (जैसे पीएम किसान) में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इस्तेमाल बढ़ाया है, जिससे सब्सिडी या लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस तरह के ट्रांसफर सिस्टम में बिचौलियों की भूमिका कम होती है और लीकेज की संभावना घटती है। सार्वजनिक खरीद-क्रय के लिए केंद्र सरकार ने जीईएम पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे बोली लगाने, ऑक्शन प्रक्रिया और लेनदेन डिजिटल रूप से हो सकते हैं। जीईएम के माध्यम से 卐इ-बिडिंग卐 और रिवर्स ऑक्शन जैसी प्रणालियां हैं, जिससे खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ी है। केंद्र सरकार के डेटा और ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम ने पिछले दशक में कुल 3.48 लाख करोड़ रूपए की बचत की है, जिसे 卐लीकेज को रोकने卐 वाला मुख्य कारक माना गया है।

संविधान ही हमें यह बताता है कि समूची व्यवस्था कैसे काम करेगी। इसके अंतर्गत चुनाव प्रणाली, सरकार का गठन (व उसका निलंबन भी), शक्तियों का बंटवारा, अधिकारों की रक्षा इत्यादि जैसे गंभीर एवं जटिल मुद्दे आते हैं। संविधान का महत्त्व इसलिए भी है कि यह सरकारों को भी दिशा दिखाने का कार्य करता है।स्वतंत्र संस्थान लोकतंत्र का सुरक्षा कवच होते हैं। यदि वे पक्षपातपूर्ण दिखने लगें, तो जनता का भरोसा डगमगाता है।चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और न्यायपालिका जैसे संस्थानों पर दबाव के आरोप सरकार पर लगते रहते हैं। कई नागरिक संगठनों और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वायत्तता और इंटरनेट प्रतिबंधों पर चिंता जताई है। भारतीय संविधान 卐सहकारी संघवाद卐 पर आधारित है। कई राज्य सरकारें शिकायत करती हैं कि केंद्र द्वारा नीतिगत और वित्तीय निर्णयों में राज्यों से पर्याप्त परामर्श नहीं लिया जाता है।एक लोकतांत्रिक समाज में न्यायिक पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। ये सिद्धांत न्यायपालिका में जनता के विश्वास की आधारशिला के रूप में काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय न केवल किया जाए बल्कि न्याय होते हुए भी दिखे। जब नागरिकों को अदालती कार्यवाही और फैसलों के बारे में जानकारी मिलती है, तो यह कानूनी व्यवस्था में समझ और विश्वास को बढ़ावा देता है। दूसरी ओर, जवाबदेही सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक जांच के रूप में कार्य करती है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद करती है।

भावना भी समझें

एक आदमी बस में रोजाना ही यात्रा करता था। वह बस में केले खाता और छिलके को खिड़की से फेंक देता। एक दिन एक भाई ने कहा, भाई! सड़क पर छिलके डालना उचित नहीं है। दूसरे फिसलकर गिर पड़ते हैं। छिलकों को एक ओर डालना चाहिए। उसने कहा, अच्छी बात है। दूसरे दिन की बात है। पूर्व दिन वाले दोनों यात्री एक ही बस में बैठे हुए थे। एक ने केले छीले, खाए और छिलके डाल दिए। सड़क पर नहीं, अन्यत्र कहीं। साथी ने कहा, धन्यवाद! कल जो मैंने कहा, उसे तुमने मान लिया। आज छिलके सड़क पर नहीं फेंके। उसने कहा, सड़क पर तो नहीं फेंके, पर मेरे पास जो दूसरा यात्री बैठा था, उसकी जेब में चुपके से छिलके डाल दिए। सड़क पर उन्हें डालने की नौबत ही नहीं आई।

हर आदमी ऐसे ही समस्या को दूसरों की जेब में डालता जाता है और यह मान लेता है कि समस्या का समाधान हो गया। समस्या सुलझती नहीं। एक समस्या सुलझती है, तो दूसरी उलझ जाती है। समस्या के समाधान का सही मार्ग है-भावनाओं पर ध्यान देना। जो भी काम किया जाता है, उसको करने से पूर्व यह सोचना होगा कि मैं यह काम शरीर की सुविधा के लिए कर रहा हूं, पर इससे कहीं मन की समस्या उलझ तो नहीं रही है? कहीं भावना की

समस्या गहरी तो नहीं होती जा रही है? हम तीनों समस्याओं पर एक साथ ध्यान दें। जब तक शरीर की समस्या, मन की समस्या और भावना की समस्या पर समवेत रूप में ध्यान नहीं देंगे, तब तक समाधान नहीं मिलेगा।

विचार मंथन

कितने हिड़मा मारोगे, हर घर से निकलेगा एक हिडमा?

(लेखक- सनत जैन)

रविवार को दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर प्रदूषण को लेकर युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया गया। इससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों के ऊपर मिर्च स्प्रे से हमला कर दिया। युवाओं ने पुलिस से बचने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों के हाथ में हाल ही में सुरक्षा बलों के एनकाउंटर में मारे गए नक्सली कमांडर हिड़मा का पोस्टर था। दिल्ली पुलिस पर किए गए मिर्च स्प्रे से दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो गए, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। पहली बार किसी विरोध प्रदर्शन में पुलिस के ऊपर मिर्च स्प्रे का उपयोग किया गया है। प्रदर्शनकारी बड़े उग्र थे। वह पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे। दिल्ली पुलिस उनसे प्रदर्शन स्थल को खाली करने की अपील कर रही थी। प्रदर्शनकारी नहीं माने। देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार इस तरह का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे, कितने हिड़मा मारोगे, हर घर से हिड़मा निकलेगा। नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला ने माना, आंदोलनकारियों का यह प्रदर्शन हिंसक था। मुट्ठी भर प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने में पुलिस को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। पहली बार पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्च स्प्रे चला गया था। उनका इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है। पुलिस कर्मियों की आंखों मे जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। एंबुलेंस में घायल पुलिसकर्मियों को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। पुलिस ने 15 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। सारे प्रदर्शनकारी पढ़े-लिखे युवा थे। इस प्रदर्शन ने दिल्ली पुलिस को चिंता में डाल दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, दिल्ली मे प्रदूषण और विभिन्न समस्याओं को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन की बाढ़ आ गई है। दिल्ली पुलिस को रोजाना प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रदर्शन इसी तरह से हिंसक होंगे तो पुलिस की परेशानी और भी बढ़ जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने कानून व्यवस्था की अनदेखी करके जिस तरह से पुलिस पर हमला करने की कोशिश की है, जिस तरह के नारे लगाए गये हैं, उसने दिल्ली पुलिस की चिंता को बढ़ा दिया है। उल्लेखनीय है दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर पहले भी युवाओं ने प्रदर्शन किया था। पुलिस ने सख्ती के साथ उसे रोक दिया था। दोबारा यह विरोध प्रदर्शन रविवार की शाम को इंडिया गेट के पास सी हेक्सागन में किया गया। दिल्ली पुलिस को अंदाज नहीं था, यह प्रदर्शन इतना उग्र हो जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आम जनमानस में भारी रोष है। युवाओं में पुलिस के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने, सड़क जाम करने का आरोप लगाया है। युवाओं में महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षाओं में परचे लीक होने तथा नौकरी नहीं मिलने के कारण भारी नाराजी है। छोटी-मोटी समस्याओं पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। आंदोलन, प्रदर्शन, धरना इत्यादि पर सरकार की दमनकारी नीति और असंवेदनशीलता से प्रदर्शनकारी उग्र हो रहे हैं। धरना-प्रदर्शन और आंदोलन के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में युवा अब विद्रोही बनकर सड़कों पर उतर रहे हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों को समय रहते करोडों पढ़े-लिखे युवा, जो कई वर्षों से बेरोजगार हैं, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है ना ही उन्हें रोजगार मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसी स्थिति में युवाओं का आक्रोश अब सड़कों पर दिखने लगा है। आंदोलनकारियों ने जिस तरह से मारे गए नक्सली कमांडर माडवी हिड़मा का पोस्टर दिखाकर आक्रोश का प्रदर्शन किया है। उन्होंने सरकार को एक तरह की चेतावनी दी है। दिल्ली में प्रदूषण की हालत एक दशक से ज्यादा समय से खराब है। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने से बीमारियां फैल रही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हर साल सरकार नए-नए दावे करती है। समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, उल्टे प्रदूषण साल दर साल बढ़ता जा रहा है। दिल्ली और देश के युवा आक्रोषित हैं। इस बार आंदोलनकारी पुलिस से मुकाबला करने की तैयारी करके आए थे। जब-जब सामाजिक असमानता बढ़ती है लोगों को पेट भरने और रहने के लिए जब भोजन और जगह नहीं मिलती है तब इस तरह के आंदोलन बड़े उग्र होते हैं। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से नक्सल आंदोलन 1970 के दशक में शुरू हुआ था। धीरे-धीरे करके यह देश के कई राज्यों में फैल गया। वर्तमान में जिस तरह से करोड़ों शिक्षित युवा और करोड़ों मजदूर बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। मनरेगा में भी इन्हें मजदूरी नहीं मिल रही है। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं मिल रही है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इसके कारण देश में सामाजिक असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। केंद्र सरकार को दिल्ली के इस आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए। लोगों की समस्याओं का समाधान हो, एक वर्ग की पूंजी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। वहीं मध्यम और निम्न वर्ग की दैनिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। करोड़ों लोग कर्ज लेकर किसी तरह से जरुरतें पूरी कर रहे हैं। महंगाई सुरसा की तरह बढ़ रही है। सरकार को समय रहते वास्तविकता को स्वीकार करते हुए गरीब और मध्यम वर्ग के लिए तुरंत कोई उपाय करने होंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भारत में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रख पाना मुश्किल होगा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

एसबीआई वेंचर्स जुटाएगा 2,000 करोड़ का जलवायु कोष

- हरित वृद्धि में निवेश को बढ़ावा देने की योजना

नई दिल्ली । एसबीआई वेंचर्स के एक अधिकारी ने आईवीसीए ग्रीन रिटर्न्स शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में बताया कि उनका उद्देश्य हरित वृद्धि को बढ़ावा देना है, जो एक नया वित्तीय अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके लिए घरेलू और वैश्विक निवेशकों से संपर्क किया जाएगा और अगले साल की शुरुआत में रोड शो आयोजित किया जाएगा। एसबीआई वेंचर्स, जो एसबीआई का वैकल्पिक संपत्ति प्रबंधक है, अपने तीसरे जलवायु-केंद्रित कोष के लिए 2,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा है। प्रभाकर ने कहा कि उनका लक्ष्य अगले कैलेंडर वर्ष की पहली तिमाही में कोष तैयार करना है। यह कोष प्रारंभिक और विकास-चरण वाले जलवायु स्टार्टअप में निवेश करेगा, विशेषकर अग्रणी जलवायु प्रौद्योगिकियों और एआई-सक्षम जलवायु नवोन्मेषण पर। प्रभाकर ने बताया कि भारत के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 170 अरब अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, जो वर्तमान प्रवाह से तीन गुना अधिक है।

जम्मू-कश्मीर में एक अरब टन चूना-पत्थर का भंडार- जीएसआई

- केंद्र का मिला समर्थन, ई-नीलामी शुरू

जम्मू । भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (जीएसआई) के अनुसार जम्मू-कश्मीर में लगभग एक अरब टन चूना-पत्थर मौजूद है। केंद्रीय खान मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजय लोहिया ने बताया कि क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की भी संभावना है, जिन्हें स्थानीय लोगों के लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली बार जम्मू-कश्मीर के खनिज ब्लॉक नीलामी मानचित्र में चूना-पत्थर ब्लॉक को शामिल करते हुए नीलामी और रोड शो का आयोजन किया गया। संजय लोहिया ने कहा कि केंद्र सरकार इस क्षेत्र में खनन, विकास और निवेश को तेज़ करने में पूरा सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने अनंतनाग, राजौरी और पुंछ में 314 हेक्टेयर में फैले सात चूना-पत्थर ब्लॉकों की ई-नीलामी शुरू की।

जेएंडके बैंक ने एमडीबी ग्रुप के साथ किया करार

नई दिल्ली । जेएंडके बैंक ने एमडीबी ग्रुप के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत मोहाली में दिल्ली-मनाली हाईवे पर विकसित हो रहे अल्ट्रा-लक्ज़री हाउसिंग प्रोजेक्ट 'द लुटियंस' के लिए विशेष वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। बैंक की ओर से एक ज़ोनल हेड (कठुआ) और एमडीबी ग्रुप की ओर से एक वे रिष्ठ सीए ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान बैंक के एक अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि यह साझेदारी बैंक की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है और प्रीमियम घर खरीदने वाले ग्राहकों को सरल, अनुकूलित और विश्वसनीय फाइनेंस सेवाएं प्रदान करेगी।

भारत हमारी एआई रणनीति के लिए महत्वपूर्ण बाजार- एनटीटी डेटा

तोक्यो । टोक्यो की वैश्विक आईटी सेवा कंपनी एनटीटी डेटा ने कहा है कि भारत उनकी एआई रणनीति में एक अहम बाजार है। कंपनी भारत को एपीएसी क्षेत्र का वैश्विक एआई आपूर्ति और प्रतिभा केंद्र बनाने पर काम कर रही है। एनटीटी डेटा के पास भारत में डेटा सेंटर क्षेत्र में 30 फीसदी हिस्सेदारी है और इसे और बढ़ाने की योजना है। कंपनी ने शुरुआती निवेश और अधिग्रहण पर गर्व जताया। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि भारत में युवा प्रतिभा को प्रशिक्षण देकर एआई रणनीति को मजबूत किया जा रहा है। इंडिया एआई मिशन जैसी सरकारी पहल कंपनी के लिए एक जरूरी समर्थन साबित हो रही है।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 313, निफ्टी 74 अंक गिरा

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के बाद भी बिकवाली हावी रहने से बाजार गिरा है। ऑटो, आईटी और निजी बैंकिंग शेयरों में मुनाफावसूली से भी बाजार पर दबाव पड़ा। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 313.70 अंक नीचे आकर 84,587.01 और 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 74.70 अंक नीचे आकर 25,884.80 पर बंद हुआ। वहीं लार्जकैप शेयरों में बिकवाली दर्ज की गयी। इसके विपरीत मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में खरीदारी रही। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 216.40 अंक याकी तेजी के साथ 60,298 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 33.80 अंक की मजबूती के साथ 17,730.30 पर था। सेक्टोरल आधार पर आज मिश्रित कारोबार हुआ। निफ्टी पीएसयू बैंक 1.44 फीसदी, निफ्टी फार्मा 0.44 फीसदी, निफ्टी मेटल 0.55 फीसदी, निफ्टी रियल्टी 1.62 फीसदी, निफ्टी कमोडिटी 0.15 फीसदीऔर निफ्टी हेल्थकेयर 0.37 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ।

वहीं दूसरी ओर निफ्टी ऑटो 0.23 फीसदी, निफ्टी आईटी 0.57 फीसदी, निफ्टी मीडिया 0.80फीसदीऔर निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.23 फीसदी नीचे आकर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में बीईएल, एसबीआई, टाटा स्टील और भारती एयरटेल के शेयर लाभ में रहे जबकि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, ट्रेंट, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, एमएंडएम और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर गिरे।

इससे पहले आज सुबह बाजार सपाट रुख के साथ खुले। सेंसेक्स ने 100 अंकों की बढ़त के साथ 85,008 पर कारोबार की शुरुआत की, लेकिन खुलते ही इसमें कमजोरी नजर आई। इसी तरह निफ्टी-50 भी 25,998 पर खुला, लेकिन जल्द ही इसमें उतार-चढ़ाव दिखा।

केंद्र की नई फास्ट ट्रैक जीएसटी योजना से पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी

- 21 मिनट में मिला जीएसटी नंबर!

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने 1 नवंबर से फास्ट ट्रैक जीएसटी पंजीकरण योजना शुरू की। इसका उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को तेज़, आसान और पारदर्शी बनाना है। जीएसटी परिषद ने सितंबर में 56वीं बैठक में इस योजना को मंजूरी दी थी। पहले 15 दिनों में 1,42,000 आवेदनों को मंजूरी मिली, जिनमें दो-तिहाई पंजीकरण स्वचालित रूप से हुए। कुल 2,17,000 पंजीकरण मंजूर किए गए। सबसे तेज मंजूरी 21 मिनट में दी गई। पहला पंजीकरण 1 नवंबर को जारी हुआ। नई प्रणाली के तहत तीन कार्यदिवसों में पंजीकरण उन आवेदकों को मिलेगा जिन्हें सिस्टम डेटा से पहचाना जा सके और जिनकी मासिक देयता 2.5 लाख रुपये से अधिक न हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, इससे 96 प्रतिशत नए आवेदकों को लाभ होगा। अधिकारियों के अनुसार, नई ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के एक अधिकारी ने बताया कि छोटे कारोबारी और पेशेवर अब 24 घंटे में पंजीकरण प्राप्त कर रहे हैं।

अमेरिका शेयर बाजारों में तेजी, सभी प्रमुख इंडेक्स बढ़त के साथ बंद

- फेड रेट कट की उम्मीदें और ट्रंप-शी बातचीत से ग्लोबल सेंटीमेंट हुआ मज़बूत

वाशिंगटन । सप्ताह की शुरुआत अमेरिकी शेयर बाजारों के लिए बेहद सकारात्मक रही, जहां सभी प्रमुख इंडेक्स मज़बूत बढ़त के साथ बंद हुए। सोमवार को डाउ जोंस में 0.44 फीसदी की उछाल दर्ज की गई, जबकि नेस्डेक ने 2.69 फीसदी की दमदार छलांग लगाई, जो 12 मई के बाद इसकी सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी रही। एसएंडपी 500 भी 1.5 फीसदी से अधिक चढ़कर बंद हुआ। इस रैली की मुख्य वजह ब्रॉडकॉम, माइक्रॉन, एएमडी और टेस्ला जैसे दिग्गज टेक शेयरों में भारी खरीदारी रही, जिसने बाजार की धारणा को काफी मजबूत किया। ग्लोबल मार्केट्स में तेजी की एक बड़ी वजह दिसंबर में फेडरल रिज़र्व द्वारा 0.25 फीसदी रेट कट की बढ़ती उम्मीदें भी हैं। बाजार विशेषज्ञों के ताजा अनुमान के अनुसार, रेट कट की संभावना 44 फीसदी से बढ़कर 70 फीसदी तक पहुंच गई है। अभी फेड फंड रेट 3.75-4.00 फीसदी के बीच है। रेट कट की संभावना बढ़ने से अमेरिका ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के बाजारों में पॉजिटिव माहौल बना है।

टेक शेयरों की तेजी से अरबपतियों की दौलत में 65 अरब डॉलर का इजाफा

वॉशिंगटन।

अमेरिकी शेयर बाजारों में सोमवार को टेक्नोलॉजी शेयरों में आई जबरदस्त तेजी ने टेक बिलियनेयर्स की संपत्ति पर भारी असर डाला। गूगल, टेस्ला, अमेजन और मेटा जैसे दिग्गज कंपनियों के शेयरों में उछाल से अरबपतियों की लिस्ट में बड़ा हलचल मच गया। इंडेक्स के अनुसार, दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों में से नौ की संपत्ति एक ही दिन में करीब 65 अरब डॉलर बढ़ गई। ये सभी अमेरिकी टेक उद्योग से जुड़े हैं, जो इस तेजी के प्रमुख लाभार्थी बने।

इस उछाल ने अमीरों की रैंकिंग को हिला दिया। गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज अब दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जिन्होंने ओरिकल के लैरी एलिसन को पीछे छोड़ दिया। गूगल के शेयर 6 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर 318.57 डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुए, जिससे पेज को 14.9 अरब डॉलर का सीधा फायदा हुआ। उनकी कुल संपत्ति अब 272 अरब डॉलर हो गई है। इसी तरह, अमेजन के जेफ बेजोस चौथे से पांचवें स्थान पर खिसक गए, जबकि निवेश के दिग्गज वॉरेन बफे टॉप-10 से बाहर हो गए।

सबसे ज्यादा लाभ टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को हुआ। टेस्ला शेयरों में 6 प्रतिशत से अधिक की तेजी से उनकी संपत्ति 19.1 अरब डॉलर उछल गई। अब मस्क की कुल दौलत 441 अरब डॉलर पहुंच गई है, जो उन्हें इस साल के शीर्ष लाभ कमाने वालों में फिर से ला खड़ा किया। मस्क ने कहा कि यह उछाल इलेक्ट्रिक वाहनों और एआई क्षेत्र में बढ़ती मांग का नतीजा है। दूसरे नंबर पर लैरी पेज के बाद गूगल के दूसरे सह-संस्थापक सर्गेई ब्रिन रहे, जिनकी संपत्ति 13.8 अरब डॉलर बढ़कर 254 अरब डॉलर हो गई। लैरी एलिसन को 3.2 अरब डॉलर का फायदा मिला, उनकी कुल संपत्ति 257 अरब डॉलर है, जिसमें इस साल 64.4 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है। अमेजन शेयरों में 2.53 प्रतिशत की बढ़ोतरी से बेजोस की दौलत 5.09 अरब डॉलर चढ़कर 248 अरब डॉलर पहुंची।

मेटा प्लेटफॉर्म्स के शेयर 3 प्रतिशत से ज्यादा ऊपर चढ़े, जिससे मार्क जुकरबर्ग ने 6.49 अरब डॉलर कमाए। उनकी संपत्ति अब 217 अरब डॉलर है। एनवीडिया के शेयरों में 2 प्रतिशत की तेजी से सीईओ जेनसन हुआंग को 3.13 अरब डॉलर का लाभ हुआ, उनकी कुल दौलत 159 अरब डॉलर हो गई। माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ स्टीव बाल्मर ने 5.87 अरब डॉलर जोड़े, उनकी संपत्ति 165 अरब डॉलर पहुंची। डेल टेक्नोलॉजीज के माइकल डेल ने 9.42 अरब डॉलर कमाकर 154 अरब डॉलर के साथ दसवें स्थान पर कब्जा जमाया और बफे को बाहर कर दिया। यह तेजी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में टेक सेक्टर की मजबूती को दर्शाती है, लेकिन विशेषज्ञ चेताते हैं कि बाजार की अस्थिरता से ये लाभ अस्थायी हो सकते हैं। फिर भी, टेक बिलियनेयर्स की यह डॉलर की बारिश वैश्विक धन असमानता पर बहस छेड़ रही है।

अफगानिस्तान सोने की खदानों में पैसा लगाएं भारतीय कंपनियां, टैक्स में मिलेगी छूट

-भारत का व्यापारिक दूत अफगान होगा तैनात, दोनों देशों में व्यापार आसान होगा

नई दिल्ली।

भारत में अफगानिस्तान के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी अपनी छह दिन की यात्रा पूरी कर ली। इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए। भारत का एक व्यापारिक दूत अफगानिस्तान में तैनात होगा जो दोनों देशों के व्यापार को और आसान बनाएगा। साथ ही जो भारतीय कंपनियां या निवेशक अफगानिस्तान के सोने की खदानों में पैसा लगाएंगी, उन्हें पांच साल तक टैक्स में पूरी छूट दी जाएगी। सबसे खास बात ये है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच एक एयर कार्गो कॉरिडोर से नया रास्ता खुलेगा। यही मुख्य बातें हैं जो तालिबान शासित अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने अपनी छह दिन की भारत यात्रा सोमवार को खत्म करते वक्त तय कीं। पिछले हफ्ते भारत आए अजीजी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य राज्य मंत्री जितिन प्रसाद से मुलाकात की थी और भारतीय कारोबारियों से बातचीत की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में अफगान दूतावास में पत्रकारों से बात करते हुए अजीजी ने कहा था कि एक महीने में अफगानिस्तान का व्यापारिक दूत भारत आएगा और काबुल चाहता है कि दोनों देशों का व्यापार एक अरब डॉलर से बहुत ज्यादा हो। उन्होंने कहा कि निजी निवेश के मामले में भारत और अफगानिस्तान दोनों तरफ से बहुत मजबूत रहे। अजीजी ने भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में पैसा लगाने का ऑफर दिया और कहा कि खदान, खेती, दवा-स्वास्थ्य, आईटी, बिजली और कपड़ा जैसे कई क्षेत्रों में मौका है। उन्होंने बताया कि नए क्षेत्रों में निवेश करने वालों को पांच साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। खासकर सोने की खदान में। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन वहां ज्यादा प्रतिद्वंद्वी नहीं मिलेंगे, भारत को जमीन भी देंगे, टैरिफ में छूट देंगे और पांच साल टैक्स माफ करेंगे, ताकि भारतीय कंपनियां आसानी से वहां कारोबार शुरू कर सकें।

छोटी और मझोली कंपनियों ने बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया

- सितंबर 2025 की तिमाही में भारत की बड़ी कंपनियों का मुनाफा धीमा रहा

मुंबई ।

सितंबर 2025 की तिमाही में भारत की बड़ी कंपनियों का मुनाफा केवल 1.2 फीसदी बढ़ा, जो पिछले तीन साल में सबसे कमजोर वृद्धि है। बिक्री में भी वृद्धि धीमी रही, केवल 6.4 फीसदी, जो पिछले 17 तिमाहियों में सबसे कम है। नतीजतन, निफ्टी-50 का कुल मुनाफे में हिस्सा घटकर 50 फीसदी रह गया, जो पिछले पांच साल में न्यूनतम है। इस तिमाही में इन कंपनियों ने मिलकर 1.81 ट्रिलियन का मुनाफा कमाया। वहीं देश की बाकी लिस्टेड कंपनियों का कुल मुनाफा 10.8 फीसदी बढ़ा। मिडकैप-150 कंपनियों का मुनाफा 27 फीसदी और स्मॉलकैप-250 का 37 फीसदी बढ़ा। इस तरह छोटी और मझोली कंपनियों ने बड़ी कंपनियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। कुल 2,647 कंपनियों का मुनाफा 3.62 ट्रिलियन तक पहुंच गया। विश्लेषकों के अनुसार, इस तिमाही में अधिक कमाई ऊर्जा, धातु, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मटेरियल और ऑटो जैसे चक्रीय सेक्टर्स से हुई। निफ्टी-50 में इन सेक्टरों की कंपनियां कम हैं। इसके बजाय, बड़ी कंपनियों में बैंक, आईटी, एफएमसीजी और तेल-गैस जैसी सेक्टर अधिक हैं, जिनकी वृद्धि इस तिमाही में धीमी रही।

क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट से ट्रंप परिवार को झटका, 8900 करोड़ हुए स्वाहा

-एरिक ट्रंप बोले- गिरावट कभी बुरी नहीं होती, यह बेहतरीन खरीदारी का मौका होती है

वाशिंगटन।

कुछ समय से क्रिप्टोकरेंसी में आई गिरावट ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार को झटके मिल रहे हैं। ट्रंप परिवार ने क्रिप्टो का बड़ा पेरोकार है। अब वही क्रिप्टो बाजार उनके समर्थकों के सामने एक कड़वा सबक बनकर खड़ा है। ट्रंप परिवार की कमाई उनकी घोषित संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कम समय में ही हवा हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक परिवार की कुल संपत्ति सितंबर की शुरुआत में 7.7 अरब डॉलर थी, जो अब घटकर 6.7 अरब डॉलर पर आ गई है यानी करीब 1 अरब डॉलर का नुकसान। ट्रंप परिवार को तो एक अरब डॉलर का ही नुकसान हुआ है पूरी दुनिया में इस क्रैश ने निवेशकों का 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान कर दिया है। अगस्त से अब तक ट्रंप के नाम से जुड़े मीम कॉइन की कीमत करीब 25फीसदी गिरी है। हालत यह है कि जिसने भी इस मीमकॉइन को इसके लॉन्चिंग के सप्ताह भर बाद खरीदा, वह अब करीब अपना पूरा निवेश गंवा चुका है। ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप की जिस बिटकॉइन माइनिंग कंपनी में हिस्सेदारी है, उसकी वैल्यू अपनी ऊंचाई से करीब आधी रह गई है। वहीं ट्रंप की सोशल मीडिया कंपनी, ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, जिसने इस साल बिटकॉइन में भारी निवेश किया था, उसके शेयर भी अपने रिकॉर्ड निचले स्तर के आसपास आ गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एरिक ट्रंप क्रिप्टोकरेंसी के कट्टर समर्थक हैं। वह लगातार समर्थकों से कहते रहे हैं कि गिरावट कभी बुरी नहीं होती, बल्कि एक बेहतरीन खरीदारी का मौका होती है। जो लोग उतार-चढ़ाव का स्वागत करते हैं,

वे ही असली विजेता बनते हैं, लेकिन उनकी ये सलाह अब निवेशकों के लिए मुसीबत बन गई है। ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, जो ट्रूथ सोशल चलाती है, ने गलत समय पर क्रिप्टो की दुनिया में बड़ा दांव लगाया। कंपनी ने करीब 2 बिलियन डॉलर बिटकॉइन और उससे जुड़े सिक्योरिटीज में लगाए थे। उस समय बिटकॉइन की कीमत करीब 115,000 डॉलर थी। अब कीमत करीब 25फीसदी नीचे है, जिससे कंपनी नुकसान में चली गई। कंपनी ने सिंगापुर से जारी सीआरओ टोकन भी बड़ी मात्रा में खरीदे थे, जिसकी कीमत अब आधी रह गई है। इसका सीधा असर ट्रंप की अपनी हिस्सेदारी पर भी पड़ा, जिसकी कीमत सितंबर से अब तक करीब 800 मिलियन डॉलर घट गई है।

एआई लॉन्चिंग से लैरी पेज बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति

- पेज की नेटवर्थ में 7.5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई

नई दिल्ली ।

अमेरिकी शेयर बाजार में हाल की उथल-पुथल के बीच गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज ने नया एआई मॉडल जेमिनी 3 लॉन्च होते ही ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में दूसरा स्थान हासिल कर लिया। लॉन्च के बाद अल्फाबेट के शेयरों में 3 फीसदी की तेजी आई, जिससे पेज की नेटवर्थ में 7.5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई और उनकी संपत्ति 257 अरब डॉलर तक पहुंच गई। लैरी पेज के पार्टनर सर्जेई ब्रिन की नेटवर्थ में 6.9 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई, और उनकी कुल संपत्ति 240 अरब डॉलर हो गई। दोनों संस्थापकों ने 1998 में गूगल की शुरुआत एक छोटे गैराज से की थी और आज एआई के दम पर कंपनी फिर से तेजी पकड़ रही है। विश्लेषकों का कहना है कि जेमिनी 3 स्टेट-ऑफ-द-आर्ट एआई मॉडल है, जो गूगल के प्रोडक्ट्स में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस लॉन्च ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया और अगले महीनों में और शेयर मूवमेंट की उम्मीद है। दुनिया के अरबपतियों की टाप-10 सूची में पहले नंबर पर एलन मस्क, दूसरे पर लैरी पेज, तीसरे नंबर पर लैरी एलिसन, चौथे जेफ बेजोस, पांचवे सर्जेई ब्रिन, छठवे मार्क जुकरबर्ग, सातवे बर्नार्ड अर्नाल्ट, आठवे स्टीव बाल्मर, नौसे जेन्सन हुआंग और 100वे नंबर पर वॉरेन बफेट का नाम शा मिल है।

बजाज ऑटो ने ई-रिक्शा 'रिकी' के साथ किया बड़े पैमाने पर विस्तार

- पहले चरण के तहत इसकी उपस्थिति आठ शहरों तक पहुंची

नई दिल्ली ।

बजाज ऑटो लिमिटेड ने इस साल अपने नए इलेक्ट्रिक रिक्शा 'रिकी' के साथ ई-रिक्शा खंड में कदम रखा है। कंपनी ने शुरू में चार शहरों में पायलट परीक्षण किया था। अब पहले चरण के तहत इसकी उपस्थिति आठ शहरों तक पहुंच चुकी है, जिनमें पटना, मुरादाबाद, गुवाहाटी और रायपुर शामिल हैं। कंपनी अगले साल जनवरी से मार्च तक 'रिकी' को 200 शहरों और कस्बों तक ले जाने की योजना बना रही है। बजाज ऑटो के एक कार्यकारी निदेशक के अनुसार शुरुआती चरण में ग्राहक प्रतिक्रिया देखी जाएगी। इसके आधार पर मात्रा और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पहले चरण में बजाज ऑटो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम के कई शहरों और कस्बों को लक्षित कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले तीन-चार महीनों में कंपनी केवल शुरुआत कर रही है, उसके बाद विस्तार की गति तेज होगी। 'रिकी' की कीमत 1.9 लाख रुपये है। कंपनी का कहना है कि यह पारंपरिक लेड-एसिड बैटरी वाले ई-रिक्शा की तुलना में अधिक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल है। एक बार चार्ज करने पर यह 140 किलोमीटर तक चल सकता है।

बजाज ऑटो ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर उत्पादन और वितरण बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है, जिससे यह ई-रिक्शा खंड में एक मजबूत मौजूदगी बना सके।

कच्चे तेल में गिरावट से रुपया 11 पैसे मजबूत, 89.05 डॉलर पर पहुंचा

डॉलर की मजबूती से दबाव बरकरार, विदेशी मुद्रा बाजार में सीमित दायरे में कारोबार

मुंबई ।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का असर मंगलवार को भारतीय मुद्रा बाजार में दिखाई दिया, जहां रुपया शुरुआती कारोबार में 11 पैसे की मजबूती के साथ 89.05 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 89.02 पर खुला और शुरुआती दौर में हल्की बढ़त दर्ज करते हुए 89.05 के स्तर पर पहुंचा। विश्लेषकों के अनुसार कच्चे तेल की नरम कीमतें रुपये को सहारा दे रही हैं, हालांकि डॉलर की वैश्विक मजबूती रुपये पर दबाव बनाए हुए है। सोमवार को घरेलू मुद्रा 50 पैसे बढ़कर 89.16 पर बंद हुई थी। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर इंडेक्स 0.06 फीसदी बढ़कर 100.13 पर पहुंच गया। वैश्विक स्तर पर ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.33 फीसदी टूटकर 63.16 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जिससे उभरते बाजारों की मुद्राओं में हलचल बढ़ी।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

टेस्ट सीरीज में वापसी की आस पर पानी फिरा, भारत को मिला 549 रनों का महा-लक्ष्य, मुश्किल में टीम

गुवाहाटी (एजेंसी)। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। दक्षिण अफ्रीका द्वारा दिए गए 549 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम ने 21 रन पर दो विकेट गंवा दिए। टेस्ट सीरीज़ में 1-0 से पिछड़ रही भारतीय टीम के सामने कल एक कठिन चुनौती है क्योंकि टेस्ट के आखिरी दिन उसके पास केवल आठ विकेट ही बचे हैं। भारत ने चौथे दिन के आखिरी सत्र में विकेट गंवाए और गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच के आखिरी दिन दक्षिण अफ्रीका की स्थिति मजबूत है।

चौथे दिन स्टंप्स तक भारत का स्कोर 27/2 था, जिसमें कुलदीप यादव (4*) और साई सुदर्शन (2*) नाबाद थे। मेज़बान टीम को दो मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर करने के लिए पाँचवें दिन 522 रनों की ज़रूरत है। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल सस्ते में आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका ने दिन की शुरुआत दूसरी पारी में 26/0 से की और लंच तक 220/4 रन बनाकर ट्रिस्टन स्टब्स (60*) और वियान मुल्डर (29*) स्ट्राइक पर थे।

लंच के बाद के सत्र में नीतीश कुमार रेड्डी ने पहला चौका तब दिया जब स्टब्स ने 74वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्हें चार चौके जड़े। स्टब्स ने आक्रामक रुख अपनाया और 76वें ओवर में रेड्डी के खिलाफ लगातार दो चौके लगाए। 78वें ओवर में, प्रोटियाज़ बल्लेबाज़ ने रवींद्र जडेजा की गेंद पर डीप मिड-विकेट की बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। 78वें ओवर की तीसरी गेंद पर, स्टब्स, जो अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, जडेजा की गेंद पर बोल्ड हो गए, जिन्होंने 180 गेंदों में 94 रन बनाए।

स्टब्स के आउट होने के बाद, दक्षिण अफ्रीका ने 260/5 पर अपनी पारी घोषित करने का फैसला किया और उन्होंने 549 रनों का मुश्किल लक्ष्य रखा। यह दूसरी बार है जब भारत को घरेलू टेस्ट में 500 से ज़्यादा रनों का लक्ष्य दिया गया है। इससे पहले 2004 में नागपुर में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 543 रनों का लक्ष्य दिया था। वह मैच वे 342 रनों से हार गए थे, जो रनों के लिहाज़ से उनकी सबसे बड़ी हार है। भारतीय सलामी बल्लेबाज़ केएल राहुल और यशस्वी बल्लेबाज़ी करने उतरे। जायसवाल ने एक चौका और एक छक्का लगाकर आक्रामक रुख़ दिखाया, जबकि राहुल ने सतर्कता से शुरुआत की।

'दीप्ति शर्मा डब्ल्यूपीएल मेगा नीलामी में सबसे ज़्यादा डिमांड वाली खिलाड़ी होंगी'

नई दिल्ली (एजेंसी)। जैसे-जैसे टीमें टाटा डब्ल्यूपीएल 2026 मेगा ऑक्शन की तैयारी कर रही हैं और अपनी टीम को मजबूत करना चाहती हैं, सभी की नजरें भारत की टॉप ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और भरोसेमंद बैट्समैन हरलीन देओल पर हैं, जो उनकी लाइन-अप को मजबूत करेंगी। जियो हॉटस्टार के शो 'मोस्ट वांटेडः टाटा डब्ल्यूपीएल 2026 ऑक्शन' में एक्सपर्ट अंजुम चोपड़ा और वेदा कृष्णमूर्ति ने दीप्ति शर्मा के ऑलराउंड असर और हरलीन देओल की वैल्यू को खास भारतीय खिलाड़ियों के तौर पर बताया, जिन पर हर फ्रेंचाइजी करीब से नजर रखेगी।

अंजुम चोपड़ा ने अपनी राय साझा करते हुए कहा, 'गुजरात जायंट्स को मेगा-ऑक्शन में दीप्ति शर्मा पर जरूर विचार करना चाहिए। दिल्ली कैपिटल्स भी उन्हें एक भारतीय खिलाड़ी के रूप में टारगेट कर सकती है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों को मजबूत करती है। गुजरात और दिल्ली के बाद यूपी वॉरियर्स उनकी सर्विस लेने में दिलचस्पी रखने वाली तीसरी टीम हो सकती है।'

गुजरात जायंट्स द्वारा हरलीन देओल को रिलीज किए जाने पर उन्होंने कहा, 'मुझे हैरानी है कि गुजरात जायंट्स ने हरलीन देओल को रिलीज किया। वह एक मल्टी-टैलेंटेड भारतीय खिलाड़ी है जो थोड़ी बॉलिंग भी कर सकती है, और मुझे उम्मीद है कि वह अपनी बॉलिंग स्किल्स को और डेवलप करेगी। ऑक्शन में उसमें अच्छी दिलचस्पी होगी। दीप्ति शर्मा के साथ, वह एक ऐसी भारतीय खिलाड़ी होगी जिसे हर फ्रेंचाइजी टारगेट करेगी क्योंकि टीमें मजबूत भारतीय बैट्समैन और संभावित लीडरशिप ऑप्शन चाहती हैं।'

वेदा कृष्णमूर्ति ने दीप्ति शर्मा की स्किल्स की तारीफ की और बताया कि मेगा नीलामी में वह सबसे ज़्यादा डिमांड वाली प्लेयर क्यों होंगी। उन्होंने कहा, 'दीप्ति शर्मा पिछले डब्ल्यूपीएल सीजन से एक जानी-मानी मैच-विनर हैं, उन्होंने बैट और बॉल दोनों से शानदार परफॉर्म किया है। उन्होंने हाल ही में खत्म हुए विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड भी जीता। मेगा-ऑक्शन में उनकी डिमांड जरूर ज़्यादा होगी, और हर फ्रेंचाइज उन पर करीब से नजर रखेगी।% टाटा डब्ल्यूपीएल 2026 की मेगा नीलामी 27 नवंबर को होगी जिसे जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधे देखा जा सकता है।

शमी की फिर हुई उपेक्षा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर समाप्त होने का संकेत तो नहीं

मुम्बई (एजेंसी)। पिछले काफी समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की एक बार फिर अनदेखी हुई है। शमी को घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के बाद भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज के लिए शामिल नहीं किया गया है। शमी लंबे समय से वापसी के लिए इंतजार रहे थे पर टीम में जगह नहीं मिलने से उनका इंतजार लंबा होता जा रहा है। इससे ये भी अटकलें लगायी जा रही हैं कि शमी अब लगता है चयन समिति की योजनाओं का हिस्सा नहीं रहे हैं। अभी वह घरेलू क्रिकेट में बंगाल की ओर से खेल रहे हैं। हाल ही में शमी ने रणजी ट्रॉफी के पहले चरण में बंगाल की ओर से 4 मैचों में 20 विकेट लिए थे और उन्हें सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के लिए भी जगह मिली थी पर इसके बाद भी उन्हें भारतीय टीम में जगह नहीं मिल पायी है। जिससे कहा जा रहा है उनका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर समाप्त हो गया है।

ये भी कहा जा रहा है कि जब शमी घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते हुए लगातार विकेट ले रहे हैं तो फिर उन्हें टीम में जगह क्यों नहीं मिल रही है। क्या चयन समित उसने अपनी नाराजगी निकला रही है। शमी ने कुछ समय पहले चयन समिति पर सवाल उठाये थे। तब मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने एक कार्यक्रम में बताया था कि उन्हें फिटनेस की वजह से टीम में शामिल नहीं किया जा रहा है। इसके बाद . शमी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वह पूरी तरह से फिट हैं और इसी कारण घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं। गौरतलब है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में आराम दिया गया है। फिलहाल ये दोनों तेज गेंदबाज टेस्ट सीरीज में खेल रहे हैं। ऐसे में शमी को अवसर दिया जाना था पर ऐसा नहीं हुआ।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में महाराष्ट्र की कप्तानी करेंगे पृथ्वी शॉ, आईपीएल में वापसी पर रहेगी नजर

नई दिल्ली (एजेंसी)। पृथ्वी शॉ एक ऐसा नाम जिसे कभी भारतीय क्रिकेट के सबसे चमकदार युवा सितारों में गिना जाता था और अब अपने करियर को फिर से जीवित करने के निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। बीते कुछ वर्षों में खराब फॉर्म, फिटनेस चुनौतियों और ऑफ-फील्ड विवादों ने उनकी प्रगति को गहरी चोट पहुंचाई। लेकिन 2025-26 घरेलू सीजन से पहले महाराष्ट्र में शिफ्ट होकर शॉ ने अपने लिए नई शुरुआत का रास्ता चुना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उनके लिए वह मंच बन सकती है, जहां वे दोबारा साबित कर सकते हैं कि उनका टैलेंट अब भी उतना ही खतरनाक है।

पृथ्वी शॉ की नई शुरुआत : बदलाव जिसने सबका ध्यान खींचा

मुंबई क्रिकेट के पोस्टर बॉय रहे पृथ्वी शॉ ने पहली बार अपने घरेलू करियर की दिशा बदलते हुए महाराष्ट्र को चुना। यह कदम न केवल उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा का संकेत देता है, बल्कि यह भी बताता है कि वे एक स्वच्छ शुरुआत और बेहतर अवसर की तलाश में हैं। वर्षों की अस्थिरता और टीम चयन में लगातार गिरावट के बाद यह बदलाव उनके करियर का अहम मोड़ माना जा रहा है।

SMAT: करियर को पटरी पर लाने का सुनहरा मौका

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT), जो टी20 फॉर्मेट में भारत के सबसे बड़े घरेलू टूर्नामेंटों में से एक है, शॉ के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। कल से शुरू होने वाला यह टूर्नामेंट उनके लिए सिर्फ रन बनाने का अवसर नहीं, बल्कि यह दिखाने का मंच है कि वे वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। IPL 2025 के मिनी ऑक्शन को देखते हुए हर पारी, हर रन और हर स्ट्राइक-रेट उनकी बोली पर सीधा प्रभाव डालेगा।

IPL ऑक्शन में झटका और अब उम्मीद की नई किरण

पिछले साल के IPL ऑक्शन में किसी भी टीम ने पृथ्वी शॉ पर बोली नहीं लगाई। यह उनके लिए सिर्फ एक पेशेवर झटका नहीं, बल्कि एक संकेत था कि उनके मार्केट वैल्यू में बड़ी गिरावट आ चुकी है। अब उनकी नज़र SMAT में दमदार प्रदर्शन पर है। अगर वे अपनी पुरानी आक्रामक बैटिंग शैली और कंसिस्टेंसी वापस लेकर आते हैं, तो IPL टीमों का ध्यान उनकी ओर लौट सकता है, खासकर वे फ्रेंचाइजी जो भारतीय ओपनर की तलाश में हैं और विदेशी स्लॉट बचाना चाहती हैं।

लीडरशिप की जिम्मेदारी

इस बार पृथ्वी शॉ को सिर्फ बल्लेबाज नहीं, बल्कि कप्तान की भूमिका भी निभानी है। रुतुराज गायकवाड़ राष्ट्रीय टीम के लिए चयनित होने के कारण महाराष्ट्र की कप्तानी ग्रुप स्टेज तक शॉ को सौंपी गई है। यह भूमिका उनके व्यक्तित्व, मैच्योरिटी और गेम अवेयरनेस को उजागर करने

का शानदार मौका है, वे गुण जिन्हें IPL टीमें बहुत महत्व देती हैं।

दिल्ली कैपिटल्स से शुरुआत और विस्फोटक IPL रिकॉर्ड

शॉ ने IPL में अपने सातों सीजन दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेले, जहां उन्होंने 1,892 रन बनाए और 147 की स्ट्राइक-रेट से गेंदबाजों पर हावी रहे। पावरप्ले में तेज शुरुआत दिलाने की उनकी क्षमता आज भी कई टीमों के लिए अमूल्य है। अगर वे पुराना फ्लो वापस पाते हैं, तो IPL 2026 से पहले उनका क्रिकेट करियर दोबारा नई उड़ान पकड़ सकता है।

ऑस्ट्रेलियाई ओपन वाइल्ड कार्ड प्लेऑफ में सुमित नागल की जीत के साथ शुरूआत

चेंगडू । भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने चीन के मिंगुइ झांग को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन एशिया पेसीफिक वाइल्ड कार्ड प्लेआफ के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। छठी वरीयता प्राप्त नागल ने 2.6, 6.0, 6.2 से जीत दर्ज की। नवंबर 24 से 29 तक होने वाले इस टूर्नामेंट में आस्ट्रेलियाई ओपन 2026 के मुख्य ड्रॉ के लिये पुरूष और महिला एकल विजेता को वाइल्ड कार्ड मिलेंगे । नागल को शुरूआत में चीन का वीजा लेने में दिक्कत आई। उनका आवेदन खारिज होने के बाद उन्हें चीनी अधिकारियों से सार्वजनिक तौर पर अपील करनी पड़ी। बाद में मसला सुलझने पर वह यहां आ सके । अब उनका सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त बू युंचाओकेते और जिजियांग यांग के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा।

भारत में खेलकर उत्साहित हैं मुथुसामी

नई दिल्ली । गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में शानदार शतक लगाने दक्षिण अफ्रीका टीम के भारतीय मूल के ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी ने कहा है कि भारत में खेलकर उन्हें बेहद खुशी हुई है। मुथुसामी ने कहा है कि साल 2019 में भारत दौरे के बाद उन्हें लगा था कि अब उन्हें यहां कभी भी टेस्ट क्रिकेट खेलने का कोई अवसर फिर कभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि तब वह दो विकेट ही ले पाये थे। इसलिए वह इस बार के भारत दौरे से बेहद उत्साहित हैं। अब 6 साल बाद मुथुसामी ने भारत दौरे में शानदार प्रदर्शन कर अपने को साबित किया है। उन्होंने कहा कि उपमहाद्वीप के हालातों को हमने बेहतर ढंग से सामझा है। मुथुसामी ने इस साल पाकिस्तान दौरे में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहले टेस्ट में ही 11 विकेट लिए थे। वहीं दूसरे टेस्ट में 89 रन की नाबाद पारी खेलीं अब उन्होंने भारत के खिलाफ 109 रन की पारी ऐसे समय में खेली जब टीम ने 201 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे। मुथुसामी ने कहा, 'मेरी यात्रा अलग प्रकार की रही है। साल 2019 में भारत से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया पर अधिक सफलता नहीं मिली हालांकि क्रिकेट एक सफर है जिसमें आप बस हर दिन को एक एक करके लेते हैं और ज्यादा आगे की नहीं सोचते।' उन्होंने कहा, 'लेकिन 2019 के बाद मुझे भरोसा नहीं था कि मैं कभी टेस्ट क्रिकेट खेल पाऊंगा। और भारत में खेलने के बारे में तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। ' मुथुसामी ने कहा, ' मैं बस उस समर्थन के लिए आभारी हूं जो मुझे कोचों, परिवार और सहयोगी स्टाफ से मिला।' साल 2019 की पदार्पण सीरीज के बाद उन्हें चार साल बाद टीम में जगह मिली। इस बीच उन्होंने घरेलू क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था।

सुल्तान अजलान शाह कप : बेल्जियम के खिलाफ 2-3 से हारा भारत

इपोह (एजेंसी)। भारतीय हॉकी टीम ने मंगलवार को मलेशिया के इपोह में सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में बेल्जियम के खिलाफ फाइटिंग परफॉर्मेंस दी, लेकिन 3-2 से हार गई। सुल्तान अजलान शाह स्टेडियम में हुआ यह हॉकी मैच पहले सोमवार को होना था, लेकिन भारी बारिश की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। भारत के लिए अभिषेक (33') और शिलानंद लाकड़ा (57') ने गोल किए, जबकि पूर्व ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम के लिए रोमन डुवेकोट (17', 57') और निकोलस डी केर्पेल (45') गोल करने वाले खिलाड़ी थे।

सातवें नंबर की टीम भारत ने पक्के इरादे से शुरुआत की, दुनिया की नंबर 3 बेल्जियम को दूर रखा और शुरुआती दबाव का सामना किया। भारतीय गोलकीपर पवन को रीस्टार्ट के दोनों तरफ एक्शन में लाया गया, जिससे उनकी टीम बराबरी पर रही और वे लगातार गेम में आगे बढ़ते रहे। बेल्जियम को मैच शुरू होने के 10 मिनट बाद पेनल्टी कॉर्नर से पहला असली मौका मिला, और जल्द ही उन्होंने दूसरा मौका भी बनाया। हालांकि, भारतीय डिफेंस ने मजबूती से खड़े होकर यह पक्का किया कि वे पहले क्वार्टर के बाद बराबरी पर रहें।

भारत ने दूसरे क्वार्टर की शुरुआत फ्रंट फुट पर की और मौके की तलाश में अच्छे पास दिए। हालांकि, बेल्जियम ने खेल के दौरान बढ़त बना ली, और रोमन डुवेकोट के गोल की मदद से पवन की रुकावट को तोड़ दिया। तुरंत जवाब की तलाश में, दिलप्रीत सिंह ने भारत के लिए एक अच्छा मूव पूरा किया लेकिन खतरनाक खेल के कारण गोल रद्द कर दिया गया। भारत के ज़ोर लगाने और जांच करने के बावजूद, बेल्जियम ने हाफ टाइम तक अपनी 1-0 की बढ़त बनाए रखी। दूसरे हाफ में भारत ने शुरुआत से ही जोरदार शुरुआत की और अभिषेक के शानदार मूव को गोल में बदलकर बराबरी हासिल की।

मोमेंटम के साथ भारतीयों ने दूसरे गोल की तलाश में बेल्जियम पर दबाव बनाया। हालांकि, निकोलस डी केर्पेल (45') ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके बेल्जियम को बढ़त वापस दिला दी। उन्होंने जल्द ही अपनी बढ़त बढ़ा ली, चौथे क्वार्टर की शुरुआत में रोमन डुवेकोट ने गोल करके बेल्जियम को कुछ राहत दी। भारत ने एक बार फिर तुरंत जवाब देने की कोशिश की और 10 मिनट से भी कम समय में पेनल्टी कॉर्नर से गोल करने के करीब पहुंच गया।

शिलानंद लाकड़ा ने कुछ देर बाद रबीचंद्र सिंह के शानदार क्रॉस पर गोल करके भारत को उम्मीद की एक किरण दी। जब मैच खत्म होने में 90 सेकंड बाकी थे, मोहित एचएस ने शानदार स्टॉप लगाकर बेल्जियम को चौथा गोल करने से रोक दिया और भारत को रेस में बनाए रखा। हालांकि, इस कड़े मुकाबले में भारत बराबरी का गोल नहीं कर पाया। पांच बार का सुल्तान अजलान शाह कप विजेता भारत अब बुधवार को मेजबान मलेशिया से खेलेगा।

विराट को टेस्ट नहीं एकदिवसीय से संन्यास लेना चाहिये था : श्रीवत्स गोस्वामी

गुवाहाटी । दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन को देखते हुए पूर्व क्रिकेटर श्रीवत्स गोस्वामी ने कहा कि अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेटर खेलना जारी रखना था। गोस्वामी ने कहा कि विराट को टेस्ट की जगह पर एकदिवसीय से संन्यास लेना चाहिये था। गोस्वामी ने कहा है कि और एकदिवसीय से संन्यास लेना चाहिये था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की ओर से खेले श्रीवत्स ने सोशल मीडिया में कहा कि विराट को टेस्ट क्रिकेट नहीं छोड़ना चाहिए था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भारतीय टीम इंडिया की खराब बल्लेबाजी के बाद गोस्वामी ने कहा कि कोहली का टेस्ट से अचानक संन्यास लेना भारतीय क्रिकेट के लिए नुकसानदेह रहा है। गोस्वामी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, मेरा मानना है कि विराट को एकदिवसीय खेलना छोड़ देना चाहिए था और टेस्ट क्रिकेट तब तक खेलते रहना चाहिए था, जब तक कि उनका फार्म बरकरार था। एक खिलाड़ी के तौर पर उनकी ऊर्जा, भारत के लिए खेलने का प्यार और जुनून टीम को हर हाल में जीतने को प्रौत्साहित करता है। गोस्वामी ने साथ ही लिखा, विराट के अंदर जीतने की जो मानसिकता और जोश था, वह वर्तमान टीम में नहीं है। गौरतलब है कि कोहली का कप्तान के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में काफी अच्छा रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने 68 टेस्ट मुकाबलों में भारतीय टीम की ओर से खेलते हुए 40 मुकाबले जीते जबकि 17 मैचों में उन्हें हार झेलनी पड़ी। विराट ने इस साल 12 मई को टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। कोहली ने अंतिम बार बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 खेली थी जिसमें वह केवल एक शतक ही लगा पाए थे। उन्होंने इंग्लैंड दौरे के पहले अचानक ही संन्यास ले लिया था।

रोहित और विराट की जोड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले ही एकदिवसीय में बनाएगी रिकार्ड

मुम्बई । भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में खेलते नजर आयेंगे। इस सीरीज में प्रशंसकों को विराट और रोहित को खेलते हुए देखने का अवसर मिलेगा। अब 30 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले एकदिवसीय में उतरते ही रोहित और विराट की जोड़ी सबसे अधिक मैच खेलने का एक नया रिकार्ड अपने नाम करेगी। रोहित और विराट ने अभी तक 391 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। किसी जोड़ी के यह संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेल सबसे अधिक मैच हैं। रोहित और कोहली के अलावा सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की जोड़ी ने भी इतने ही मैच खेले थे। ऐसे में जब रोहित और विराट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला एकदिवसीय खेलने मैदान पर उतरेंगे तो वह तेंदुलकर और द्रविड़ के इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। रोहित-कोहली की जोड़ी इस मैच में उतरते ही भारत के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली जोड़ी बन जाएगी। सचिन और सौरव गांगुली की जोड़ी 341 मैचों में एकसाथ उतरी थी। वहीं सचिन और अजहर की जोड़ी 292 मैचों में उतरी। विराट कोहली और महेन्द्र सिंह धोनी की जोड़ी 285 मैचों में उतरी।

पलाश की बहन बोली , मंधाना और हमारे परिवार की निजता का सम्मान करें

इंदौर । भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज स्मृति मंधाना के पिता को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी शादी टल गयी है। इसी मामले को लेकर अब स्मृति के मंगेतर पलाश मुच्छल की बहन पलक ने लिखा है कि शादी टल गयी है। इस संवेदनशील समय में हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें। स्मृति की शादी का कार्यक्रम रविवार को था पर उनके पिता को सीने में दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा जिसके बाद स्मृति के पिता को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और शादी की तैयारियां रोक दी गयीं। इसके बाद स्मृति के मंगेतर पलाश मुच्छल की तबीयत भी खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें भी अस्पताल ले जाना पड़ा हालांकि कुछ समय में इलाज के बाद वह होटल लौट आये। .प्लाश को वायरल संक्रमण और एसिडिटी बढ़ने के कारण एक निज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद पलाश को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वहीं मंधाना परिवार के डॉक्टर नमन शाह ने बताया कि उनकी सेहत की निगरानी के लिए मेडिकल टीम तैनात है। अगर उनकी तबीयत में जरूरी सुधार होता है तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। अचानक आई इन मुसीबतों से परिवार उबर रहा है और चाहता है कि इन क्षणों में उसकी निजता का सम्मान किया जाये।

भारतीय बल्लेबाजों की नाकामी कोच की गलती नहीं : सुरेश रैना ने गौतम गंभीर का किया बचाव

नई दिल्ली(एजेंसी)। भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने आलोचनाओं से घिरे राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर का समर्थन करते हुए कहा है कि घरेलू टेस्ट मैचों में टीम के हालिया खराब प्रदर्शन के लिए सहयोगी स्टाफ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि खिलाड़ियों को नतीजों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पिछले साल न्यूजीलैंड के हाथों घरेलू मैदान पर बुरी तरह हारने के बाद भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा श्रृंखला में भी एक और निराशाजनक परिणाम की ओर बढ़ रहा है।

दो मैचों की इस श्रृंखला का पहला मैच गंवाने के बाद भारत के पास अब दूसरे मैच को जीतने की संभावना बेहद कम है। रैना ने कहा, 'गौती भैया (गौतम गंभीर) ने बहुत मेहनत की है और इसमें (टेस्ट टीम की मौजूदा स्थिति) उनकी कोई गलती नहीं है। खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत करनी होगी और अच्छा खेलना होगा। उनके नेतृत्व में हम सीमित ओवरों के प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां हमने इस साल की शुरुआत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और दुबई में एशिया कप जीता था।'

'भारतीय सॉफ्टबॉल क्रिकेट लीग' के जर्सी लॉन्च के मौके पर इसके ब्रांड एम्बेस्डर रैना ने कहा, 'रन तो खिलाड़ियों को ही बनाने होंगे। कोच मार्गदर्शन और सलाह ही दे सकता है।' रैना ने उन सुझावों को खारिज कर दिया कि घरेलू टेस्ट मैचों में खराब प्रदर्शन के कारण मुख्य कोच के रूप में गंभीर का भविष्य खतरे में है। उन्होंने कहा, 'खिलाड़ियों को अगर कोई समस्या आ रही है, तो उन्हें कोच से इस बारे में बात करना चाहिए। खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो कोच की भी सराहना की जाएगी। लेकिन टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, तो कोच को उसके पद से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए।'

उन्होंने कहा, 'मैं गौतम भैया के साथ खेला हूं, उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम से प्यार है, उन्हें क्रिकेट से प्यार है, मैंने उनके साथ विश्व कप खेला है और जीता भी है। उन्होंने देश के लिए वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है और अच्छा प्रदर्शन करना खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है।' मौजूदा श्रृंखला में भारतीय टीम के चयन से जुड़े फैसलों की आलोचना पर रैना ने कहा कि घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन ही मानक बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा, 'खिलाड़ियों को नियमित रूप से घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए और वहां अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, अगर वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रदर्शन में अपने आप दिखाई देगा।'

उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में खिलाड़ियों के लिए तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूप से सामंजस्य बिठाना काफी चुनौतीपूर्ण है। व्यस्त कार्यक्रम का असर प्रदर्शन पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 'इस श्रृंखला के लिए बेहतर योजना बनाई जा सकती थी क्योंकि खिलाड़ियों को सफेद गेंद (सीमित ओवर) प्रारूप से लाल गेंद (टेस्ट) प्रारूप में ढलने का काफी कम समय मिला।'

रैना ने कहा कि वह 30 नवंबर से शुरू होने वाली दोनों टीमों के बीच वनडे श्रृंखला का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें टीम को बेहर अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा का साथ मिलेगा। उन्होंने कहा, 'रो-को (रोहित शर्मा और विराट कोहली)' जरूर वापसी करेंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन किया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे टीम को जरूर मजबूत करेंगे। ये दोनों विश्व और भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन दूत हैं। जब वे टीम में होंगे तो माहौल अलग होगा, ऋषभ पंत भी कुछ समय बाद वापसी कर रहे हैं, इसलिए वनडे श्रृंखला देखना मजेदार होगा।'

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी पर 2 पर्वतारोहियों की मौत, 2 को बचाया

वेलिंगटन, एजेंसी। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी आओराकी पर दो पर्वतारोहियों की मौत हो गई, जबकि उसी समूह के दो अन्य को बचा लिया गया। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस क्षेत्र कमांडर इंस्पेक्टर विकी वॉकर ने बताया कि मृत पर्वतारोहियों के शव मिल गए हैं और विशेषज्ञ खोजकर्ता उन्हें 'एक चुनौतीपूर्ण अल्पाइन वातावरण में' खोजने के लिए काम कर रहे हैं। किसी भी पर्वतारोही की सार्वजनिक रूप से पहचान नहीं की गई है। सार्जेंट केविन मैकएरलेन ने द टिमारू हेराल्ड को बताया कि जब वे माउंट कुक के नाम से भी जाने जाने वाले आओराकी के शिखर के पास गिरे तो दोनों को एक रस्सी से बांध दिया गया था। स्थानीय समयानुसार सोमवार देर रात अधिकारियों को पता चला कि न्यूज़ीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित इस पर्वत पर चार पर्वतारोहियों को मदद की जरूरत है। वॉकर ने बताया कि मंगलवार सुबह तड़के हेलीकॉप्टर से दो पर्वतारोहियों को बचा लिया गया। वे सुरक्षित थे। दो हेलीकॉप्टरों में खोजकर्ता रात भर अन्य पर्वतारोहियों की तलाश करते रहे, जो कुछ घंटों बाद मृत पाए गए।

स्लोवेनिया : जनमत संग्रह में खारिज हुई इच्छामृत्यु

ल्युब्ल्याना, एजेंसी। स्लोवेनिया के लोगों ने एक जनमत संग्रह में उस कानून को खारिज कर दिया, जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित लोगों को अपना जीवन खत्म करने की अनुमति देता था। चुनाव प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रारंभिक नतीजों में यह जानकारी सामने आई। लगभग पूरी हो चुकी मतगणना के अनुसार, करीब 53% मतदाताओं ने इस कानून के खिलाफ मतदान किया जबकि लगभग 46% ने इसके पक्ष में वोट दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान लगभग 50% रहा। इच्छामृत्यु के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करने वाले रूढ़िवादी कार्यकर्ता एलेस प्रिम्क ने कहा, करुणा की जीत हुई है। स्लोवेनिया ने जहर देकर मौत की नीति पर आधारित सरकारी स्वास्थ्य, पेंशन और सामाजिक सुधारों को अस्वीकार कर दिया है। यूरोपीय संघ (ईयू) के इस छोटे से देश की संसद ने यह कानून जुलाई में पारित किया था। पिछले वर्ष हुए एक गैर-बाध्यकारी जनमत संग्रह में लोगों ने इसका समर्थन किया था।

पाकिस्तान : खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया

क्वेटा, एजेंसी। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सोमवार को खुफिया जानकारी पर आधारित अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने तीन अफगान आतंकवादियों को मार गिराया। विश्वसनीय सूचना के आधार पर खैबर जिले के मदियांक क्षेत्र में यह अभियान चलाया गया। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भीषण गोलीबारी हुई, जिसके परिणामस्वरूप तीन आतंकवादी मारे गए, जबकि दो अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मारे गए सभी आतंकवादी अफगान नागरिक थे, जो सीमा पार कर आए थे। उनके कब्जे से हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान क्षेत्र में शांति बहाल करने तथा आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। इसके अलावा, दक्षिण वजीरिस्तान जिले में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के कारण हुए विस्फोट में एक युवा चरवाहे की मौत हो गई।

ब्राजील : प्राइड मार्च में बोल्सोनारो को जेल भेजने पर खुशी

रियो डी जेनेरियो, एजेंसी। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो की सालाना 'प्राइड परेड' के लिए कोपाकबाना के बोर्डवॉक पर हजारों लोग जुटे और देश के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को एक दिन पूर्व एहतियाती तौर पर जेल भेजे जाने का जश्न मनाया। प्रदर्शनकारी ट्रकों पर सवार थे और उन्होंने लोगों से कहा, बोल्सोनारो जेल में हैं। उन्होंने इसी खुशी में 'बोल्सोनारो बाहर जाओ' जैसे नारे भी लगाए। बोल्सोनारो को 2022 की चुनावी हार के बाद सत्ता में बने रहने के लिए तख्तापलट की कोशिश करने के जुर्म में सितंबर में 27 वर्ष की सजा सुनाई गई थी।

फिलीपीन : फ्लड प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार में सात और पकड़े गए

मनीला, एजेंसी। फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा कि अधिकारियों ने बाढ़ नियंत्रण परियोजनों (फ्लड प्रोजेक्ट) से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सात और संदिग्धों को हिरासत में लिया है और अन्य की तलाश जारी है। लगभग 48 लाख डॉलर के घोटाले में स्थानीय कांग्रेस यानी संसद के कई पूर्व प्रतिनिधि और लोक निर्माण विभाग के एक दर्जन से अधिक अभियंता शामिल हैं। मामले के सामने आने के बाद गरीबी से जूझ रहे दक्षिण-पूर्व एशियाई देश में एक बार फिर गुस्सा उबल रहा है।

पाकिस्तान ने आधी रात अफगानिस्तान में 3 एयरस्ट्राइक की

घर पर बमबारी में 10 लोगों की मौत, इनमें 9 बच्चे और एक महिला

काबुल, एजेंसी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। सोमवार रात को पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में एक नागरिक के घर पर बमबारी की, जिसमें 9 मासूम बच्चों और एक महिला की मौत हो गई। तालिबान सरकार ने इसे पाकिस्तानी आक्रमण करार देते हुए कड़ी निंदा की है। बताया जा रहा है कि यह हमला पेशावर में रविवार को हुए एक सुसाइड बॉम्बिंग के जवाब में किया गया, जिसमें पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय पर हमला हुआ था। मंगलवार को तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सोमवार देर रात करीब 12 बजे खोस्त प्रांत के गोरबुज जिले के मुगलगेई क्षेत्र में पाकिस्तानी हमलावर सेना ने एक स्थानीय नागरिक, वलियत खान (काजी मीर के बेटे) के घर पर बमबारी की। इस हमले में 9 बच्चे- 5 लड़के और 4 लड़कियां मारे गए। इस्लामिक अमीरात सरकार के डिप्टी स्पोक्सपर्सन हमदुल्ला फिरात ने बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका में एयर स्ट्राइक की, जिसमें चार आम नागरिक घायल हो गए।

कई घायल, सीमा क्षेत्रों में तनाव बढ़ा : एएफपी के अनुसार, कुनर और पक्तिका के सीमा इलाकों पर हुए अन्य हमलों में चार नागरिक घायल हुए हैं। पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि आतंकवादी अफगान धरती से उसके खिलाफ हमलों की योजना बनाते और उनका संचालन करते हैं, जिसे तालिबान सरकार खारिज करती आई है।

हमलों के कुछ ही घंटों बाद हुई अहम मुलाकात : हमलों के बीच दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कई महीनों बाद पहली उच्च-स्तरीय बातचीत हुई। डॉन अखबार के अनुसार, पाकिस्तान के कौंसुल जनरल (जलालाबाद) शफकतुल्लाह खान ने नंगरहार के गवर्नर मुल्?ला मोहम्मद नईम अखुंद से मुलाकात की।

यह बैठक ऐसे समय हुई जब पाकिस्तान के पेशावर में फेडरल कॉन्स्टेबुलरी मुख्यालय पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें तीन कर्मियों की मौत हो गई और सुरक्षाबलों ने हमलावरों को मार गिराया। हमले ने सुरक्षा स्थिति को लेकर पाकिस्तान में चिंताएं और बढ़ा दी हैं।

तालिबानी मंत्री की भारत यात्रा : इस बीच, अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अल्हाज नूरुद्दीन आजीजी भारत की राजधानी नई दिल्ली में हैं। यह उनकी 5 दिवसीय यात्रा का हिस्सा है, जो 19 नवंबर को शुरू हुई। यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। भारत और अफगानिस्तान ने सोमवार को कपड़ा व्यापार बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। अफगानिस्तान ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कपास उत्पादक देश के रूप में भारत की विशेषज्ञता का लाभ उठाने में रुचि जतायी है। आर्थिक संबंध महानिदेशक शफीउल्लाह आजम के नेतृत्व में अफगानिस्तान के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने कपड़ा मंत्रालय के व्यापार सलाहकार ए. बिपिन मेनन के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ यहां बैठक की।

पाकिस्तान खुद भी सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा : यह हमला ऐसे समय हुआ जब पाकिस्तान खुद भी सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा था। इसी शाम पाकिस्तान के पेशावर शहर में फ्रंटियर कांस्टेबुलरी मुख्यालय पर हमला हुआ। यह मुख्यालय सैन्य कैंट क्षेत्र के पास स्थित है। इस आत्मघाती हमले में 6 लोग मारे गए, जिनमें 3 कमांडो और 3 हमलावर शामिल हैं। कई लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर खुद को चादर से ढककर पहुंचा था। उसने चौकी पर पहुंचते ही खुद को उड़ा लिया। इसमें 3 पुलिसकर्मी मारे गए।

तनाव से तालमेल की ओर बढ़े भारत-कनाडा के रिश्ते, मंत्री बोलीं- व्यापार समझौते को फिर गति देने की तैयारी

टोरंटो, एजेंसी। भारत और कनाडा के रिश्तों में दो साल की तनातनी के बाद संबंध सुधरते नजर आ रहे है। जी20 में पीएम कार्नी और पीएम मोदी की बैठक के बाद दोनों देशों ने रुकी हुई ट्रेड डील बातचीत फिर शुरू करने पर सहमति जताई है। ऐसे में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने कहा कि कनाडा नई विदेश नीति के तहत भारत के साथ व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाएगा, ताकि बदलते वैश्विक माहौल में आर्थिक साझेदारी मजबूत की जा सके।

विदेश मंत्री अनीता आनंद ने इस बात पर भी जोर दिया कि कनाडा और भारत जल्द ही नई व्यापारिक साझेदारी (ट्रेड डील) पर तेजी से काम आगे बढ़ाएंगे। पिछले दो साल से दोनों देशों के संबंध तनाव में थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। आनंद ने बताया कि कनाडा ने अपनी विदेश नीति को भी बदला है, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना किया जा सके।

भारत-कनाडा व्यापार का भविष्य : विदेश मंत्री अनीता आनंद ने आगे कहा कि दोनों देश उम्मीद कर रहे हैं कि 2030 तक आपसी व्यापार को बढ़ाकर 50 अरब अमेरिकी डॉलर कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कनाडा अभी भारत का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत में महत्वपूर्ण विदेशी निवेशक भी। कार्नी अगले साल भारत की यात्रा करेंगे।

समझिए तनाव की वजह क्या थी : बता दें कि दोनों देशों के संबंध 2023 से तब से खराब चल रहे थे, जब कनाडाई पुलिस ने आरोप लगाया था कि वैंकूवर के पास एक सिख कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका थी। निज्जर, जो कनाडा में पल्याम्बिंग व्यवसाय चलाते थे और खालिस्तान आंदोलन से जुड़े थे, जून 2023 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा में रहने वाले चार भारतीय नागरिक इस हत्या के मामले में गिरफ्तार हैं और मुकदमे का इंतज़ार कर रहे हैं। इस विवाद के बाद 2023 में कनाडा ने भारत के साथ व्यापार वार्ता रोक दी थी। हालांकि तनाव के बाद 2024 में रिश्ते सुधारने के संकेत मिलने लगे। जून में पीएम कार्नी ने मोदी को अल्बर्टा में जी7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। अगस्त में दोनों देशों ने अपने शीर्ष राजनयिकों को वापस नियुक्त किया। अनिता आनंद ने कहा कि पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं।

इस्राइली पीएम नेतन्याहू का भारत दौरा फिर टला

तेल अवीव, एजेंसी। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस साल के अंत में भारत की यात्रा पर आने वाले थे, लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने अपनी इस यात्रा को टाल दिया है। उनकी यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए तय की गई थी। सूत्रों के अनुसार, यह कदम नई दिल्ली में हुए एक भयानक आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा कारणों से उठाया गया है। इस हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो नेतन्याहू अब अगले साल नई तारीख तय करेंगे, जब सुरक्षा परिस्थितियों का आकलन हो जाएगा। बता दें कि इस बार को लगाकर इस साल इस्राइली पीएम नेतन्याहू ने तीन बार भारत की यात्रा रद्द की है। पहले उन्होंने नौ सितंबर को भारत यात्रा रद्द की थी। इसका कारण था इस्राइल में 17 सितंबर को होने वाले चुनाव और उससे जुड़े कार्यक्रम। इसके पहले अप्रैल में भी उनकी यात्रा रद्द हो गई थी।

नेतन्याहू की भारत यात्रा, मजबूत छवि बनाने की कोशिश : नेतन्याहू का भारत यात्रा इस्राइल में उनके वैश्विक स्वीकार्यता दिखाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा था। कारण है कि इस साल जुलाई में उनकी पार्टी ने नेतन्याहू की पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ तस्वीर वाले पोस्टर लगाकर उनकी छवि को मजबूत करने की कोशिश की थी। हालांकि इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है कि उनका चुनाव अभियान हमेशा से यह दिखाने पर केंद्रित रहा है कि वह दुनिया के नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं, जो कि इस्राइल की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पीएम मोदी गए थे इस्राइल : गौरतलब है कि नेतन्याहू ने भारत की पिछली यात्रा जनवरी 2018 में की थी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी 2017 में तेल अवीव गए थे और वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जो इस्राइल गए। दोनों नेताओं के करीबी रिश्तों की अक्सर भारतीय और इस्राइली मीडिया में चर्चा होती रही है।

अपने ही बोझ से दब सकता है पाकिस्तान, आबादी ही कराएगी बर्बादी

इस्लामाबाद, एजेंसी। दुनिया के कई देश घटती आबादी के संकट से परेशान हैं। इटली, जापान, रूस, साउथ कोरिया जैसे देशों में तेजी से आबादी कम हो रही है और हालात ऐसे हैं कि अस्तित्व के संकट तक की बात हो रही है। यहां तक कि भारत जैसे देश में भी अब प्रजनन दर तेजी से कम हो रही है। प्रति महिला जन्मदर अब भारत में 1.9 ही रह गई है, लेकिन पाकिस्तान की आबादी में तेजी से विस्फोट हो रहा है। बदलते दौर में भी पाकिस्तान की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, उससे देश के आगे संकट पैदा हो सकता है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने ही अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट में पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था ही चरमराने का अनुमान जताया है।

पाकिस्तान की बढ़ती आबादी और उसके संसाधनों में असंतुलन का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का 33वां देश है। लेकिन आबादी के मामले में वह 5वें नंबर पर पहुंच गया है। कराची, लाहौर,

पेशावर, रावलपिंडी, क्वेटा समेत तमाम शहरों की हालत यह है कि जरा सी बारिश भी बाढ़ जैसे हालात पैदा कर देती है। भारी आबादी के चलते कहीं भी रिहायश की सही व्यवस्था नहीं है और खेती का रकबा भी लगातार कम हो रहा है। क्लाइमेट चेंज और आर्थिक संकट जैसी समस्याएं अलग से घर रही हैं। फिलहाल पाकिस्तान की आबादी 241.5 मिलियन पर है।

अब यह अगले 5 सालों में 300 मिलियन यानी 30 करोड़ तक पहुंच गई है। यही नहीं 2050 में तो यह 40 करोड़ हो जाएगी। छोटे से देश की इतनी भीषण आबादी बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में प्रजनन दर 3.6 है। यह भारत के मुकाबले लगभग दोगुनी है। साउथ एशिया के देशों में किसी भी मुल्क की आबादी बढ़ने की ग्रोथ इतनी अधिक नहीं है। पाकिस्तान के बाद अफ्रीका के मुल्कों में ही आबादी बढ़ने की रफ्तार इतनी तेज देखी जा रही है।

डॉन के मुताबिक इतनी भारी आबादी का असर हर सेक्टर पर दिख रहा है। एक तरफ बच्चे कुपोषित हैं तो वहीं उनके बड़े होने पर बेरोजगारी का संकट है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और हेल्थकेयर जैसी समस्याएं भी पैदा हो रही है। पाकिस्तान की बढ़ती आबादी के चलते हालात यह हैं कि 5 साल से कम आयु के 40 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं। इसके अलावा बच्चों को जन्म देने के दौरान ही 11 हजार माताओं की हर साल मौत हो जाती है। पाकिस्तान में गर्भ निरोधक उपायों के इस्तेमाल में कमी के चलते भी ऐसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसकी वजह कुछ लोगों की कट्टरता है और वे गर्भनिरोध का इस्तेमाल नहीं करते। यही नहीं यह कट्टरता बढ़ती आबादी में एक और तरीके से खाज का काम करती है। पोलियो की दवा का विरोध किया जाता है और इसके चलते अक्सर पाकिस्तान में पोलियो के केस मिल जाते हैं।

'ट्रंप ने कह दिया है- अमेरिकी लोगों को ही देनी होंगी नौकरियां': व्हाइट हाउस

वॉशिंगटन, एजेंसी। एच-1बी वीजा की फीस को लेकर मचे बवाल के बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का बड़ा बयान सामने आया है। लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय नौकरियों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का यह बयान एच-1बी वीजा की बढ़ती जांच और विदेशी श्रमिकों की वजह से प्रमुख उद्योगों में अमेरिकी नौकरियां के विस्थापन की संभावना पर सामने आया है।

लेविट ने कहा कि ट्रंप ने विदेशी कंपनियों को अमेरिका में सीधे निवेश करने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने इन विदेशी कंपनियों से कहा है कि आप यहां निवेश कर रहे हैं अगर आप यहां व्यापार करना चाहते हैं तो आपको अमेरिकी लोगों को ही नौकरियां देनी होंगी।

कैरोलिन लेविट ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी कर्मचारियों को बदले जाने का समर्थन नहीं करते हैं। राष्ट्रपति चाहते हैं कि अमेरिकी मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग पहले से कहीं अधिक बेहतर तरीके से चले। ये उसी का हिस्सा है, जिसके तहत राष्ट्रपति टैरिफ का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल और दुनियाभर में अच्छे व्यापार सौदे में कटौती के जरिए कर रहे हैं।' एच-1बी वीजा से जुड़ी चिंताओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक एच-1बी वीजा के मुद्दे की बात है तो इस पर राष्ट्रपति की राय सूक्ष्म और व्यावहारिक है। उन्होंने कहा कि अगर विदेशी कंपनियां अमेरिका में खरबों रुपयों का निवेश कर रही हैं और बैटरी जैसे उत्पादों को बनाने के लिए विदेशी कामगारों को ला रही हैं तो राष्ट्रपति चाहते हैं कि उन कारखानों को शुरुआत में ही चालू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति इन नौकरियों में अमेरिकी लोगों को देखना चाहते हैं।

बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा योजना के बचाव में कहा था कि उन्हें अपने कंजर्वेटिव दोस्तों और मागा समर्थकों से प्यार है। हालांकि, उन्होंने माना था कि अमेरिका में विदेशी कुशल कामगारों की जरूरत है।

यूएस-सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में 20 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने समर्थकों की ओर से की जा रही आलोचना का जवाब दिया था। उन्होंने तर्क देते हुए कहा था कि उन्नत तकनीक में भारी निवेश कर रही कंपनियां एक कंप्यूटर चिप फैक्ट्री यूं ही नहीं खोल सकती हैं और फिर बेरोजगारों की कतार से लोगों को नौकरियां दें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि विदेश विशेषज्ञों को जाने से पहले अमेरिकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है।

घर पर नजरबंद पूर्व राष्ट्रपति बोलसोनारो ने निगरानी उपकरण से की छेड़छाड़, अब जेल में बंद किए गए

साओ पाउलो, एजेंसी। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सजायाफ्ता पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो की हिरासत को बरकरार रखते हुए उनके खिलाफ सख्ती दिखाई है। कोर्ट का यह फैसला बोल्सोनारो के उस कबूलनामे के बाद आया, जिसमें उन्होंने घर में नजरबंदी के दौरान अपनी एड़ी पर लगाए गए निगरानी उपकरण को तोड़ने की कोशिश की बात स्वीकार की। अदालत ने इसे फरार होने और 27 साल की सजा से बचने का प्रयास माना। 70 वर्षीय बोल्सोनारो को गिरफ्तारी के बाद शनिवार सुबह ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में संघीय पुलिस मुख्यालय में जेल में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट की चार जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से तय किया कि उन्हें एहतियाती हिरासत में ही रखा जाए। शनिवार को गिरफ्तारी का वारंट जारी करने वाले जस्टिस अलेसांद्रे दे मोरायस ने कहा कि बोल्सोनारो फरार होने का जोखिम पैदा करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति पर 2022 के चुनाव में लुइज इनासियो लूला डीसिल्वा से हारने के बाद सत्ता में बने रहने के लिए तख्तापलट की कोशिश का आरोप है, जिसके तहत उन्हें 27 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। दे मोरायस के फैसले को उनके साथी जज फ्लावियो डीनो, क्रिस्टियानो जैनिन और कार्मेन लूसिया ने ऑनलाइन सत्र के दौरान मंजूरी दी। रविवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान बोल्सोनारो ने एक सहायक जज से कहा कि दवाइयों में बदलाव के कारण उन्हें घबराहट और भ्रम की स्थिति हुई और उनकी मानसिक हालत बिगड़ गई। इसके चलते

उन्होंने निगरानी उपकरण तोड़ने की कोशिश की। उनके डॉक्टरों और वकीलों ने यही दावा दोहराया। हालांकि, अपने आदेश में जज मोरायस ने लिखा कि बोल्सोनारो ने गंभीर अनुचित व्यवहार में मॉनिटर तोड़ने की बात स्वीकार की है। वे लगातार एहतियाती शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं और अदालत के प्रति स्पष्ट निरादर दिखा रहे हैं।' जज को बताया गया कि एड़ी पर लगे उपकरण को शनिवार को स्थानीय समयानुसार 12.08 बजे छेड़ा गया था, जिसके कुछ घंटे बाद गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया। बोल्सोनारो अगस्त से घर में नजरबंदी पर थे। शनिवार को यह जानकारी सामने आने के बाद से समर्थक व विरोधी दोनों देशभर के कई शहरों में सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि, सोमवार को बारिश के बीच ब्रासीलिया में संघीय पुलिस मुख्यालय के सामने कुछ ही प्रदर्शनकारी नजर आए। सड़क से गुजरते वाहन चालक भी कभी बोल्सोनारो के खिलाफ तो कभी लूला के समर्थन में हॉर्न बजाते रहे। संसद का सत्र फिर से शुरू होने के साथ ही तनावपूर्ण सप्ताह की तैयारी चल रही है। इसी बीच, पूर्व राष्ट्रपति के बेटे और सीनेटर फ्लावियो बोल्सोनारो ने कहा कि वह अपने पिता के लिए आम माफी बिल लाने की कोशिश जारी रखेंगे।

डोनाल्ड ट्रंप को शी जिनपिंग ने फोन पर कहा- ताइवान हमारा होगा, बस यही उसका भविष्य है

ताइपे, एजेंसी। चीन और अमेरिका के बीच संबंधों में हालिया नरमी के बावजूद ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर उभर आया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत करते हुए स्पष्ट कर दिया कि ताइवान को लेकर चीन के रुख में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा, 'ताइवान हमारा होगा। यही उसका भविष्य है। ताइवान की चीन में वापसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने अंतरराष्ट्रीय ढांचे का हिस्सा है। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार, शी जिनपिंग ने ट्रंप से कहा कि ताइवान का चीन में विलय उस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से जुड़ा है, जो अमेरिका-चीन की साझी लड़ाई के बाद बनी थी। चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है और आवश्यक होने पर बल प्रयोग करने की चेतावनी भी देता रहा है, जबकि ताइवान की लोकतांत्रिक सरकार इस दावे को सख्ती से खारिज करती है। चीनी मीडिया एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, शी ने ट्रंप से कहा कि अमेरिका और चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर फासीवाद और सैन्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसलिए, ताइवान का चीन में विलय- पोस्ट-वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर का हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा चीन के लिए रेड लाइन है और कोई भी हस्तक्षेप अस्वीकार्य होगा।

ट्रंप ने ताइवान पर नहीं की टिप्पणी : हालांकि ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ताइवान का जिक्र नहीं किया और केवल अमेरिका-चीन संबंधों को बेहद मजबूत बताया। लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ट्रंप ने फोन कॉल के दौरान स्वीकार किया कि ताइवान का मसला चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

व्यापार समझौते पर आगे बढ़ने का संदेश : फोन कॉल के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापारिक मुद्दों पर भी चर्चा की। हाल ही में

दक्षिण कोरिया में हुई बैठक में अमेरिका और चीन ने अपनी महीनों से जारी व्यापार जंग में अस्थायी नरमी दिखाई थी। चीन ने महत्वपूर्ण खनिजों पर कुछ निर्यात प्रतिबंधों को एक साल के लिए निलंबित करने पर सहमति जताई थी, जबकि अमेरिका ने चीनी सामानों पर कुछ टैरिफ घटाने और चीन को बड़ी मात्रा में अमेरिकी सोया खरीदने की अनुमति देने की घोषणा की थी।

शी जिनपिंग ने वार्ता के दौरान कहा कि दोनों देशों को इस गति को बरकरार रखना चाहिए और दक्षिण कोरिया में हुई बैठक ने चीन-अमेरिका संबंधों के विशाल जहाज की दिशा सुधारने में मदद की है। ट्रंप ने भी सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा- हमारी दक्षिण कोरिया बैठक के बाद दोनों पक्षों ने आपसी समझौतों को अपडेट रखने में अच्छी प्रगति की है। अब हम बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

दुर्लभ खनिजों पर साझेदारी की कोशिश : अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने हाल में कहा था कि वाशिंगटन थैंक्सगिविंग तक चीन के साथ दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति को लेकर एक समझौता अंतिम रूप देना चाहता है। दुर्लभ खनिजों के खनन और प्रसंस्करण पर चीन की वैश्विक पकड़ है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रक्षा क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

ताइवान ने चीन को दिया स्पष्ट संदेश : मंगलवार को ताइवान के प्रधानमंत्री चो जोंग-ताई ने बीजिंग के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि चीन में किसी भी तरह की वापसी ताइवान के 2.3 करोड़ नागरिकों के लिए कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा- रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान, एक पूर्णतः संप्रभु और स्वतंत्र देश है। 23 मिलियन लोगों के लिए 'वापसी' कोई विकल्प नहीं है- यह बिल्कुल स्पष्ट है। पिछले कुछ हफ्तों में ताइवान को लेकर चीन और जापान के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया है। दरअसल जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने हाल ही में यह संकेत दिया था कि ताइवान पर किसी हमले की स्थिति में जापान सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है। इस बयान पर बीजिंग ने कड़ा रुख अपनाया है। इसके चलते जापान में चीनी पर्यटकों की संख्या घटी है, जापानी समुद्री खाद्य पर प्रतिबंध लगाया गया है और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। दोनों नेताओं की बातचीत में यूक्रेन युद्ध भी शामिल रहा। ट्रंप ने कई बार इस संघर्ष को समाप्त करने पर जोर दिया है। चीन खुद को इस युद्ध का तटस्थ पक्ष बताता है और उसने बातचीत के माध्यम से समाधान का समर्थन दोहराया।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़सेट एफपी, 149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास, भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

एसआईआर करते-करते 23 बीएलओ की मौत, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब

कोर्ट ने केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु मामलों को लेकर की सुनवाई

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले में 23 बीएलओ की मौत के आरोपों पर गंभीर चिंता जताई. पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की ओर से पेश वकील ने इस संबंध में जानकारी दी, जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा। सुप्रीम कोर्ट में केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े मामलों को लेकर सुनवाई जारी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच सुनवाई कर रही है। केरल में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह इस मामले में अलग से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल

करे। कोर्ट ने कहा कि चूंकि केरल में अभी स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए एसआईआर प्रक्रिया को टालने की मांग पर बिना आयोग को सुने कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर तय की गई है।

वहीं पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई है। राज्य की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया में अत्यधिक दबाव के कारण अब तक 23 बीएलओ की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु में एसआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।

पाक ने किया था उरी हाइड्रो प्लांट पर हमला, सीआईएसएफ ने किया नाकाम, सम्मानित हुए जवान

नई दिल्ली

पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के पास स्थित भारत के उरी पनबिजली संयंत्र को निशाना बनाया था। हालांकि, यह हमला विफल कर दिया गया और कोई नुकसान नहीं हुआ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने बयान में यह जानकारी दी है। सीआईएसएफ ने अपने उन 19 कर्मियों को सम्मानित किया, जिन्होंने उस रात अपनी असाधारण बहादुरी और पेशेवर प्रदर्शन से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा की। सीआईएसएफ के महानिदेशक ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इन 19 कर्मियों को प्रतिष्ठित महानिदेशक डिस्क से सम्मानित किया, जो बल के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। सीआईएसएफ के अनुसार, भारतीय सेना ने 6-7 मई 2025 की दरमियानी रात को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें नागरिकों की जान गई थी। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय क्षेत्र पर तीव्र और अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। सीआईएसएफ कर्मियों ने गोलाबारी के बीच आवासीय परिसरों के पास जाने वाले गोलों के बावजूद, नागरिकों को घर-घर जाकर निकाला और सुरक्षित बंकरों में पहुंचाया। एक अधिकारी ने बताया कि लगभग 250 नागरिकों को बिना किसी जान-माल के नुकसान के सुरक्षित निकाला गया।

एलओसी से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित उरी हाइड्रो-पावर प्रोजेक्ट को भी इस दौरान निशाना बनाया गया। कमांडेंट रवि यादव के नेतृत्व में सीआईएसएफ की कुछ यूनिट ने भीषण गोलाबारी के बावजूद असाधारण साहस, धैर्य और पेशेवर प्रदर्शन का प्रदर्शन किया।

प्रधानमंत्री स्वयं संविधान के वास्तविक अर्थ और मूल्यों को समझें

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संविधान दिवस पर पीएम मोदी के संदेश पर कसा तंज

नई दिल्ली

संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी संदेश को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने महत्वपूर्ण बताया, लेकिन साथ ही तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री स्वयं संविधान के वास्तविक अर्थ और मूल्यों को समझें और उनका पालन करें, तो यह देश और आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक लाभदायक होगा।

कांग्रेस सांसद इमरान की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जबकि पीएम मोदी ने संविधान दिवस पर देशवासियों को एक खुला पत्र लिखकर संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूकता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में व्यापक भागीदारी का आह्वान किया था। एक बातचीत में मसूद ने कहा, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वह सही और महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर वह खुद संविधान का अर्थ समझें, इसका उल्लंघन न करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर न करें, तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बेहतर होगा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किए जाने की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में संविधान सभा

के योगदान को याद करते हुए अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के प्रमुख डॉ. बीआर अंबेडकर सहित अन्य सदस्यों, विशेष रूप से महिला सदस्यों की भूमिका का उल्लेख किया।

जब लोकतंत्र दांव पर हो तो लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल्यवान मार्गदर्शन की रक्षा करनी चाहिएः सीएम ममता

कोलकाता

पश्चिम बंगाल की तेज तर्रार सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि जब लोकतंत्र दांव पर हो, धर्मनिरपेक्षता ''खतरे में हो'' और संघवाद को ''ध्वस्त किया जा रहा हो'' तो लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल्यवान मार्गदर्शन की रक्षा करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि संविधान राष्ट्र की रीढ़ है, जो भारत की संस्कृतियों, भाषाओं और समुदायों की विविधता को कुशलतापूर्वक एक साथ पिरोता है।

सीएम ममता ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि आज इस संविधान दिवस पर मैं हमारे महान संविधान और भारत में हमें जोड़ने वाले महान दस्तावेज के प्रति गहरा सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। मैं आज हमारे संविधान के दूरदर्शी निर्माताओं विशेष रूप से इसके वास्तुकार डॉ बी आर आंबेडकर को भी श्रद्धांजलि देती हूं। उन्होंने संविधान सभा में रहे बंगाल के सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने संविधान को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। सीएम ममता ने कहा कि मेरा मानना है कि हमारा संविधान हमारे राष्ट्र की रीढ़ है, जो हमारी संस्कृतियों, भाषाओं और समुदायों की अपार विविधता को कुशलतापूर्वक एक एकीकृत, संघीय ढांचे में पिरोता है। इस पवित्र दिन पर हम अपने संविधान में निहित मूल लोकतांत्रिक मूल्यों

के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की फिर पुष्टि करते हैं और उन पवित्र सिद्धांतों की सतर्कतापूर्वक रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो हमें एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करते हैं और बनाए रखते हैं।

हमारा संविधान दुनिया में भारत के लोकतांत्रिक अस्तित्व की सुरक्षा दीवार बना

राज्यपाल बोस ने कहा- हम सबको संविधान पर गर्व, जो कसौटी पर खरा उतरा

कोलकाता

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बुधवार को कहा कि भारतीय संविधान अपने निर्माण के बाद से समय की कसौटी पर खरा उतरा है और दुनिया में भारत के लोकतांत्रिक अस्तित्व की सुरक्षा दीवार बना है। उन्होंने कहा कि हम सभी को भारत के संविधान पर गर्व है। यह एक विस्तृत रूप से तैयार किया गया संविधान है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है और यह साबित करता है कि भारत के संविधान के दायरे में राष्ट्र सुरक्षित है।

पीएम मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर नागरिकों को एक पत्र लिखा, जिसमें संवैधानिक कर्तव्यों पर ज्यादा ध्यान देने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में व्यापक भागीदारी का आह्वान किया। अपने संदेश में, पीएम मोदी ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली संविधान सभा और डॉ बी आर अंबेडकर के नेतृत्व वाली प्रारूप समिति के कार्यों को याद किया। उन्होंने सभा की महिला सदस्यों के योगदान का भी उल्लेख किया। पीएम मोदी ने 2010 का उल्लेख किया, जब संविधान ने 60 साल पूरे किए थे और कहा कि इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में गुजरात में संविधान गौरव यात्रा का आयोजन किया गया था।

उन्होंने कहा कि पिछले साल संविधान की 75वीं वर्षगांठ संसद के एक विशेष सत्र और देश भर में सार्वजनिक कार्यक्रमों के साथ मनाई गई थी। पीएम ने कहा कि इस साल का संविधान दिवस सरदार वल्लभभाई पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के साथ मेल खाता है। उन्होंने कहा कि रियासतों के एकीकरण में पटेल की भूमिका और अनुच्छेद 370 से जुड़े फैसले संवैधानिक प्रक्रियाओं से जुड़े थे। उन्होंने अनुच्छेद 51ए में मौलिक कर्तव्यों पर अध्याय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये कर्तव्य सामाजिक और आर्थिक विकास को दिशा प्रदान करते हैं।

संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच है, शक्ति और उनकी आवाज है

खड़गे और राहुल गांधी ने देशवासियों को दी संविधान दिवस की शुभकामनाएं

नई दिल्ली

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। खड़गे ने एक्स पर लिखा- संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का माध्यम है और इसकी भावना हमेशा एक समान रहती है। उन्होंने लिखा- संविधान सभा के सभी महान नेताओं के बहुमूल्य योगदान को हम याद करते हैं। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू व बाबासाहेब अंबेडकर जैसे अनगिनत राष्ट्रनायकों ने नवीन भारत के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

खड़गे ने आगे लिखा- आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत संविधान के बुनियादी सिद्धांतों, न्याय, समानता, आजादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को बचाने की है। आज संविधान दिवस पर हम यह प्रण लेते हैं कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए, प्रेम और भाईचारे के लिए, सौहार्द और सद्भाव के लिए लोकतंत्र और संविधान की स्वतंत्रता कायम रखेंगे। जय हिंद।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा- भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, यह देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। वादा कि चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा। संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच है, उनकी शक्ति है और हर एक नागरिक की आवाज है।

बंगाल की खाड़ी में सिस्टम सक्रिय, तटवर्ती इलाकों में मंडरा रहा साइक्लोन का खतरा

अंडमान-निकोबार में सबसे पहले दिखेगा असर, विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी

कोलकाता

बंगाल की खाड़ी में सिस्टम एक्टिव होने की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया है। मोंथा चक्रवात के बाद अब देश के तटवर्ती इलाकों में एक और साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में फिर से नया सिस्टम सक्रिय हो रहा है। इस वजह से साइक्लोन सेनयार के और मजबूत होकर आगे बढ़ने की संभावना है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि सेनयार चक्रवाती तूफान का रूट क्या होगा और इससे कौन-कौन से राज्यों पर असर पड़ेगा। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म से पश्चिम बंगाल के साथ ही ओडिशा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों के तटवर्ती इलाकों के प्रभावित होने की आशंका है। यह भी जानकारी दी है कि मलक्का जलडमरूमध्य और दक्षिण अंडमान सागर के पास बना लो-प्रेशर एरिया बुधवार को बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात का रूप ले सकता है। इसका नाम सऊदी अरब ने सेनयार रखा है, जिसका मतलब है शेर। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी यह तय नहीं है कि चक्रवात किस दिशा में जाएगा। यह बंगाल की खाड़ी के मौसम को जरूर प्रभावित करेगा, लेकिन यह तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ेगा या ऊपर मुड़कर ओडिशा या बांग्लादेश की तरफ जाएगा। इस पर साफ अनुमान नहीं है। इसका रूट तब और साफ होगा जब यह सिस्टम पूरी तरह चक्रवात में तब्दील हो

जाएगा। पूर्वी तट पर लोगों से सावधान रहने और सरकारी सलाह का पालन करने को कहा गया है।

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह पर सबसे पहले इस सिस्टम का असर नजर आएगा। यहां 28 नवंबर तक भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। निकोबार द्वीप में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। हवाओं की रफ्तार 35-45 किमी/घंटा रह सकती है, जो कुछ समय में 55 से 65 किमी/घंटा तक जा सकती है। आईएमडी के मुताबिक तमिलनाडु, केरल और माहे में भारी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भी बारिश होने का अनुमान है। कई इलाकों में बहुत भारी बारिश होने का भी अनुमान लगाया गया है।

एनएचआरसी ने रेलवे को जारी किया नोटिस, ट्रेनों में सिर्फ हलाल मांस क्यों परोसा जा रहा, मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भारतीय रेलवे में केवल हलाल-प्रोसेस्ड मांस परोसे जाने की शिकायत पर गंभीर संज्ञान लिया है।

इस मामले पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत एक्शन टेकेन रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने के निर्देश दिए हैं।

शिकायत 21 नवंबर को दर्ज की गई थी और 24 नवंबर को आयोग की बैठक में इसे रखा गया। एनएचआरसी की पीठ, जिसकी अध्यक्षता सदस्य प्रियांक कानूंगो कर रहे थे, ने इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत

संज्ञान में लिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि भारतीय रेलवे केवल हलाल मांस ही नॉन-वेज विकल्प के रूप में उपलब्ध कराता है। उनका कहना है कि यह नीति धार्मिक आधार पर भेदभाव करती है और यात्रियों की स्वतंत्र पसंद का उल्लंघन करती है। शिकायत में यह भी कहा गया कि इससे हिंदू और सिख यात्रियों को उनके धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोजन नहीं मिल पाता, जिससे उनके धार्मिक अधिकार, समानता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित होती है। इसके अलावा, हलाल मांस की अनिवार्यता हिंदू अनुसूचित जाति समुदाय के पारंपरिक मीट व्यापार और उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। एनएचआरसी ने कहा कि यह मुद्दा जीविका के अधिकार और गैर-भेदभाव के संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत प्रतीत होता है। शिकायत में संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(जी), 21 और 25 का उल्लंघन बताया गया है।

संक्षिप्त समाचार

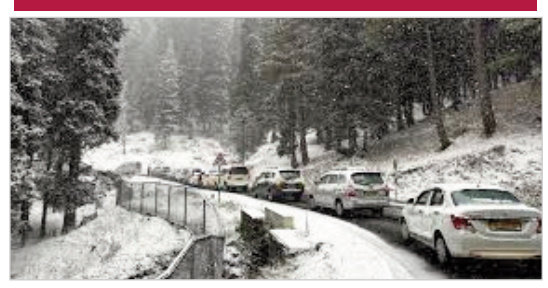

जम्मू-कश्मीर में सर्दी का प्रकोप, श्रीनगर में तापमान माइनस 3.9 डिग्री पहुंचा

श्रीनगर जम्मू-कश्मीर में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है और पहाड़ी इलाकों में गलन पैदा करने वाली ठंड का मौसम बन गया है। बुधवार को श्रीनगर में इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जब तापमान माइनस 3.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान और अधिक गिर सकता है। अधिकारियों के अनुसार, 10 दिसंबर तक गलन पैदा करने वाली ठंडी हवाएं चलेंगी, लेकिन मौसम शुष्क और साफ रहेगा। वहीं, गुलमर्ग और पहलगाम में तापमान शून्य से 4.6 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। जम्मू-कश्मीर के अन्य शहरों के तापमान की बात करें तो जम्मू 8.8डिग्री, बनिहाल 0.7डिग्री, कटरा 8.5डिग्री, बटोत 4.6डिग्री और भद्रवाह 0.5डिग्री दर्ज किया गया है। सर्दी के असर को देखते हुए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और पर्यटकों के लिए प्रशासन भी जगह-जगह अलाव की व्यवस्था कर रहा है। कई इलाकों में धुंध और घने मौसम की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। बढ़ती ठंड और बर्फबारी के कारण बच्चों के लिए स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है। इसके मद्देनजर, आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए शीतकालीन अवकाश 1 दिसंबर से शुरू किए गए हैं, जबकि कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए अवकाश 11 दिसंबर से लागू होंगे।

गूगल मीट हुई ठप, यूजर्स नहीं कर पा रहे वीडियो कॉल, शिकायतों की आई बाढ़

नई दिल्ली गूगल का पॉपुलर फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म भारत में ठप हो गया है। इसकी शिकायत करने के लिए यूजर्स ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। भारत के सैंकड़ों यूजर्स इससे प्रभावित हुए हैं। इस आउटेज से कई यूजर्स वीडियो कॉल नहीं कर पाए या उसे होस्ट नहीं कर पाए क्योंकि प्लेटफॉर्म में बड़े पैमाने पर आउटेज हुआ। यूजर्स का कहना है कि स्क्रीन पर एरर मैसेज दिखाई दे रहा है। आउटेड को ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर ने दोपहर 12:08 बजे तक 1700 आउटेज रिपोर्ट रिकॉर्ड की थीं, जिसमें 67फीसदी यूजर्स ने वेबसाइट से जुड़ी दिक्कतों को फ्लैग किया और 32फीसदी ने सर्वर से जुड़ी दिक्कतों की शिकायत की, जिससे गूगल मीट के खिलाफ शिकायतों में तेजी से बढ़ोतरी दिखती है। यह एक हफ्ते बाद हुआ जब एक बड़ी टेक्निकल दिक्कत के बाद इंटरनेट के कई हिस्से डाउन हो गए थे। एक्स पर यूजर्स शिकायत कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि यह समस्या बड़े पैमाने पर है। लोग पूछ रहे हैं क्या गूगल मीट सबके लिए डाउन है? और गूगल मीट डाउन क्यों है? कई ट्वीट में टैग करके सफाई मांगी गई। कई लोगों ने यह भी सवाल किया, गूगल मीट डाउन है! इस महीने हर बड़ी टेक कंपनी क्यों डाउन हो रही है? एक और ने कहा कि इस महीने हर बड़ी टेक कंपनी डाउन हो रही है। मैं अभी भी जीसीपी आउटेज का इंतजार कर रहा हूं। एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि क्या गूगल मीट किसी और के लिए भी डाउन है? पिछले हफ्ते लगातार सर्विस में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इन दिक्कतों की वजह से कई इलाकों के सैकड़ों यूजर्स उन वेबसाइट और सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाए जो कंपनी के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर थीं। यह बताने के बाद कि एक छिपी हुई सॉफ्टवेयर कमी ने उसके सिस्टम पर असर डाला है, सोशल नेटवर्क एक्स और एआई चैटबॉट चैटजीपीटी समेत बड़े प्लेटफॉर्म में बड़े पैमाने पर दिक्कतें आईं।

मुंबई एयरपोर्ट पर फर्जी भारतीय पासपोर्ट के साथ नेपाली महिला गिरफ्तार

मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ओमान जाने की कोशिश कर रही एक नेपाली महिला को फर्जी भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई आव्रजन अधिकारियों की सतर्कता के चलते संभव हो सकी। सहार पुलिस थाना क्षेत्र के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि पिछले सप्ताह यह महिला मस्कट जाने वाली उड़ान में सवार होने के लिए आव्रजन काउंटर पर पहुंची थी। उसने अपना नाम काजल बताया और भारतीय पासपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें उसका जन्म स्थान नोहरा, हिमाचल प्रदेश अंकित था। अधिकारी के अनुसार, महिला की शारीरिक बनावट और बोली से शक पैदा हुआ कि वह भारतीय नहीं है। संदेह होने पर उसे विस्तृत पूछताछ के लिए संबंधित अधिकारियों के पास भेजा गया। पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया कि वह भारतीय नहीं बल्कि नेपाल की नागरिक है। आगे की जांच में उसने अपना वास्तविक नाम काजल लामा बताया और कहा कि वह नेपाल के परसा जिले की रहने वाली है। महिला ने बताया कि उसके माता-पिता वर्षों पहले नेपाल से हिमाचल प्रदेश आकर बस गए थे और इसी पृष्ठभूमि का लाभ उठाकर उसने हिमाचल प्रदेश के एक फर्जी पते पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक प्रमाणपत्र बनवा लिया था।